

संक्षिप्त समाचार

गडकरी के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाना पड़ा भारी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, टोयोटा और इथेनॉल को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी फैलाना कुछ चर्चित चेहरों को भारी पड़ गया है। नागपुर शहर की साइबर पुलिस ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत चार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर अपनी पोस्ट और वीडियो के जरिए सरकार को छवि खराब करने और आम जनता के बीच भ्रम फैलाने का गंभीर आरोप लगा है। यह पूरी कार्रवाई नागपुर शहर के बीजेपी सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष शिशिर त्रिपाठी की शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत मिलने के बाद नागपुर शहर साइबर पुलिस थाने में यूट्यूबर मनीष कश्यप, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देसी बाँयज हर्षित राठी और अंकलेश इनवाते के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

अगले छह दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। मौसम विभाग ने अगले छह दिनों में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में मौनसून के एक्टिव रहने का अनुमान लगाया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बने नए लो-प्रेशर एरिया के असर से कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस बीच, दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, जिसके बाद 19 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। दिल्ली में बड़े पैमाने पर बारिश के लिए 19 जुलाई तक इंतजार करना होगा। उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधि इस सप्ताह के अंत में मजबूत होने से पहले शुरूआत में बिखरी हुई रहने की उम्मीद है। आईएमडी के अनुसार अगले कुछ दिनों में जम्मू- कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है। 19-20 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश काफी व्यापक होने की उम्मीद है,

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के चलते एक माह बंद रहेगा लाल किला

नई दिल्ली। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला 15 जुलाई से आम जनता के लिए एक महीने के लिए बंद कर दिया गया है। यहां 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का हवाला देते हुए 15 अगस्त तक लाल किला बंद करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान पर्यटकों को ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लाल किला अब 15 अगस्त के बाद आम लोगों के लिए खुलेगा। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

भूपेश के सवालों पर घिरे ओपी...

फर्जी ग्राम सभा के प्रस्तावों पर प्लांट की अनुमति

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि फर्जी ग्राम सभा के प्रस्तावों के आधार पर ग्राम अल्ट्रा में 'बालाजी स्पंज एवं आयरन लिमिटेड' तथा ग्राम देवरी-घुलघुल में 'अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड' को प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई। बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में थाने में दोषी सरपंच, पंचायत सचिव एवं प्लांट मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जगह अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज की गई। बघेल ने समूचे मामले में वित्त एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के सामने कई सवाल खड़े किए। लंबी चर्चा के बाद मंत्री के

जवाबों से अंसतुष्ट सारे कांग्रेस विधायक सदन से वाक आउट कर गए।प्रश्नकाल में भूपेश बघेल का सवाल था कि क्या यह सही है कि जनपद पंचायत तिल्दा के ग्राम अल्ट्रा में 'बालाजी स्पंज एवं आयरन लिमिटेड' तथा ग्राम देवरी-घुलघुल में 'अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड' की स्थापना, विस्तार, पर्यावरण ए.ओ.सी. या भूमि आर्बेटन/डायवर्सन हेतु ग्रामसभा प्रस्ताव शासन को मिले ? यदि हाँ, तो कम्पनियों के तहत एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई समिति ने जांच की ? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन किस तिथि को सौंपा गया और



उसमें क्या पाया गया ? जांच के आधार पर 17 जून 2026 तक कम्पनियों के प्रबंधकों, सॉलिस अधिकारियों व दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई गई ? सरकार कूटर्चित प्रस्तावों के आधार पर जारी समस्त स्वीकृतियां

निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध कब तक ठोस कार्रवाई करेगी ?वित्त एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी.चौधरी की ओर से जवाब आया कि मेसर्स बालाजी स्पंज एण्ड आयरन लिमिटेड ग्राम- अल्ट्रा, जिला- रायपुर एवं मेसर्स अग्रसेन स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ग्राम-देवरी-घुलघुल

जिला-रायपुर व्दारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सम्मति प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया गया। ग्राम सभा का कोई भी प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त नहीं हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद पंचायत तिल्दा के ग्राम अल्ट्रा को ग्राम सभा प्रस्ताव में जालसाजी की शिकायत पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तिल्दा तथा तत्कालीन नायब तहसीलदार व तत्कालीन तहसीलदार तिल्दा नेवरा की तीन सदस्यीय संयुक्त समिति ने 6 जून 2025 को जांच की।

सदन में आगे इस मसले पर कुछ इस तरह बहस चली

भूपेश- जमीन का मामला है। राजस्व, पंचायत, उद्योग होते हुए अंतिम बात आपके पर्यावरण विभाग पर आती है। इसीलिए प्रश्न पर्यावरण मंत्री से है। आपके जवाब में कार्यवाही पंजी में अंतिम दो तारीखें दिखाकर लिखी गई है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होने का उल्लेख है। वास्तविकता यह है कि शिकायत ग्रामीणों की तरफसे हुई थी।

ओ.पी.- जैसा कि स्पष्ट है बहुत से विभागों की भूमिका है। पर्यावरण विभाग का दो रेटेज में इन्वास्टमेंट है। यह स्पष्ट हो चुका है कि कंपनी की तरफसे कोई आवेदन नहीं लगा था। ग्राम पंचायत व्दारा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया था। पंचायत विभाग से जानकारी मांगी गई तो ज्ञात हुआ, गलत तरीके से ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित हुआ। 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच की, फिर एफआईआर हुई।

गाय को माता नहीं मानने वाले सत्ता में बैठे लोग

हिंदू हृदय सम्राट् नहीं हो सकते:अविमुक्तेश्वरानंद

गोंडा। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में बड़े पैमाने पर पशु हत्या और मांस का व्यापार हो रहा है। गोरक्षाई धर्मयुद्ध यात्रा के दौरान गोंडा पहुंचे शंकराचार्य ने बुधवार देर शाम एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,सत्ता में बैठे लोग हिंदू हृदय सम्राट् नहीं हो सकते क्योंकि वे गाय को माता नहीं बल्कि पशु मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन-जिन मंदिरों में संध और सरकार के लोग बैठे हैं, वहां कार्यकर्ताओं के बड़े हुए खर्चे और शौक पूरे करने के लिए मंदिरों के धन पर नजर गड़ा जा रही है। राम



मंदिर के चढ़ावे को लेकर उन्होंने तंज कसा कि वहां चोरी नहीं बल्कि पहले से सेट किए गए कलाकारों द्वारा कलाकारी की गयी है। अमरनाथ में मात्र पांच दिन में शिवालिंग के अंतर्धान होने के लिए भी शंकराचार्य ने भाजपा सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया।



नोएडा के सेक्टर 66 स्थित मामूरा गांव में पांच मजि़ला रहस्यशी इमारत के स्टिल पार्किंग एरिया में आग लगने के बाद फायरफाइटर्स ने बचाव अभियान चलाया।

3 महीने पहले ही बनी थी सांसद

टीएमसी सांसद मल्लिक ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा

नई दिल्ली/ एजेंसी

राज्यसभा में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि कोयल मल्लिक अप्रैल महीने में ही टीएमसी से राज्य सभा सांसद बनी थी। इससे पहले टीएमसी के 3 और राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली वह चौथी सांसद हैं। उनके इस्तीफे के बाद संसद में



ममता गुट के 17 सांसद बचे हैं। इससे पहले इस्तीफा देने वाला तीनों सांसद बीजेपी जाइन कर चुके हैं। अभिनेत्री से राजनेता बनीं पश्चिम बंगाल से टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा

सौंप दिया है। इसके बाद राज्यसभा में झूझ के सांसदों की संख्या घटकर 9 रह गई। कोयल मल्लिक का इस्तीफा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के करीबी मदन मित्रा के पार्टी छोड़ने के एक दिन बाद आया है। हालांकि, कोयल मल्लिक के इस्तीफे की वजह सामने नहीं आ पाई है, न ही उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को भेजे पत्र में इस वजह का जिक्र किया है। इससे पहले सुखेन्द्र शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। चर्चा है कि कोयल इस्तीफा देने के बाद उन्हें दिल्ली में भाजपा नेता भूपेंद्र यादव के घर पर देखा गया था

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को गाती देने वाला लॉ स्टूटेंट गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई के दौरान कथित अभद्र व्यवहार और हंगामा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने लॉ के दो छात्रों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रबल प्रताप और चंदर भान के रूप में हुई है। दोनों लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि (लॉ) के छात्र बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस मामले में तिलक मार्ग थाने में सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा स्टाफ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला 10 जुलाई का है, जब प्रबल प्रताप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी।

राजनाथ सिंह के घर बनेगी रणनीति

संसद सत्र से पहले एनडीए की अहम बैठक आज होगी

नई दिल्ली/ एजेंसी

संसद का मानसून सत्र अगले सप्ताह से शुरू होगा। ऐसे में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की विधायी कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए अहम बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एनडीए के नेता जुटेंगे और रणनीति बनाएंगे। सूत्रों के अनुसार, संसद के मानसून सत्र से पहले शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि एनडीए नेता आने वाले संसदीय सत्र के लिए



गठबंधन की रणनीति बनाएंगे। मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 19 जुलाई को सुबह 11 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। उम्मीद है कि इसमें सरकार अपनी मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में बताएगी, जबकि विपक्ष कई विवादास्पद

मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं, 21 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। यह बैठक सुबह 9.30 बजे संसद पुस्तकालय भवन के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी। आगामी सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। संभावनाएं हैं कि विपक्ष नीट पेपर लीक मामले को उठाएगा और 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हुई मौतों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों पर सवाल करेगा। कांग्रेस पहले ही रक्षा मंत्री के खिलाफ विरोधाधिकार का नोटिस दे चुकी है। इस बार संसद के दोनों सदनों में कई हदयंत्रों की सीट बदलने की संभावना भी है।

भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा

राज्यपाल डेका और सीएम साय ने निभाई छेरा-पहरा की परंपरा

रायपुर। संवाददाता

राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में आयोजित भव्य रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए। दोनों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पारंपरिक 'छेरा-पहरा' की रस्म निभाते हुए प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। वैदिक मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और जयघोष के बीच भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं

को विशेष विधि-विधान के साथ मंदिर से रथ तक लाया गया। इसके पूर्व राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारंपरिक रीति से सोने की झाड़ू द्वारा छेरा-पहरा की रस्म निभाकर रथमार्ग का प्रतीकात्मक शुद्धिकरण किया। इसके पश्चात महाप्रभु की प्रतिमाओं को श्रद्धापूर्वक रथ पर विराजित किया गया और रथयात्रा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को रथयात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, लोकपरंपरा और जन-जन की आस्था का महापर्व है। यह उत्सव समाज को सेवा, समर्पण, समानता और लोककल्याण का संदेश देता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा



कि भगवान जगन्नाथ किसानों के आराध्य और अन्नदाता के रक्षक माने जाते हैं। उनकी कृपा से समय पर वर्षा होती है, खेतों में हरियाली आती है, धान की बालियों में दूध भरता है और किसानों के समानता और लोककल्याण का संदेश देता है। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की

कि इस वर्ष प्रदेश में भरपूर वर्षा हो, कृषि समृद्ध हो, किसानों की मेहनत सफल हो और छत्तीसगढ़ निरंतर विकास एवं खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का दिव्य आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों पर

बना रहे तथा सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का संचार हो। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ समाज में सद्भाव, एकता और सामूहिक चेतना को भी नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष पुरी की विश्वविख्यात रथयात्रा की तर्ज पर यह आयोजन अत्यंत श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होता है। छेरा-पहरा की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि भगवान के समक्ष सभी समान हैं और सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। उल्लेखनीय है कि ओडिशा का पड़ोसी राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ में भगवान जगन्नाथ के प्रति विशेष श्रद्धा और आस्था रही है।

पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति तीन श्रद्धालुओं की मौत

ओडिशा के पुरी में मंगलवार को आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान गैड रोड पर भारी भीड़ उमड़ने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। अधिकारियों के अनुसार, भीड़ और घक्का-मुक्की के कारण करीब 120 श्रद्धालुओं को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्पेशल रैम्ब्यू यूनिट (रक) को टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। प्रभावित श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद पुरी मेंडिउल अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी 120 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना में तीन लोगों की मौत होने का दावा किया गया है।

नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय से हिन्दू जागरण मंच ने की सौजन्य भेंट

धमतरी। हिन्दू जागरण मंच जिला धमतरी के जिला संयोजक पुरुषोत्तम निषाद के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने जिले की नवपदस्थ जिला पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय से मुलाकात कर उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इस अवसर पर हिन्दू जागरण मंच के प्रतिनिधिमंडल ने जिले से जुड़े विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर जिला पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट कराया। आगामी श्री गणेश स्थापना एवं गणेश उत्सव के संबंध में चर्चा करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने सनातन धर्म की मूल परंपरा के अनुरूप मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं को बढ़ावा देने तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि मिट्टी की प्रतिमाएं पर्यावरण के संरक्षण के साथ-



साथ भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप भी हैं। जिला पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना तथा सामाजिक सौहार्द, कानून व्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। मुलाकात के दौरान हिन्दू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने संगठन द्वारा समाजहित, राष्ट्रहित, गौ-संरक्षण, सांस्कृतिक जागरण एवं सनातन

मूल्यों के संरक्षण हेतु किए जा रहे विभिन्न कार्यों से भी जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। इस अवसर पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य युवा आथाम दीपक सिंह ठाकुर, जिला सहसंयोजक चित्रेश साहू, डकेश्वर साहू, प्रतीक सोनी, सनत साहू, युवा आथाम जिला संयोजक सत्यम सिन्हा, नगर संयोजक अभिषेक साहू, नगर सहसंयोजक संजय साहू एवं शिवांश पटवा उपस्थित रहे।

शहर की यातायात व्यवस्था का किया निरीक्षण

धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बढ़ते यातायात दबाव, पार्किंग व्यवस्था, जाम की स्थिति एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को और अधिक सुचारु एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने यातायात प्रभारी को नियमित मॉनिटरिंग, प्रमुख चौक-चौराहों पर प्रभावी ड्यूटी, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा आमजन को सुरक्षित एवं सुगम यातायात उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार धमतरी पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक ने थाना सिटी कोतवाली धमतरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीसीटीएनएस कार्य, थाना अभिलेखों के संधारण, मालखाना, कार्यालयीन व्यवस्थाओं, थाना परिसर एवं भवन की साफ-सफाई का अवलोकन किया तथा अभिलेखों को अद्यतन रखने, कार्यालयीन कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने एवं थाना परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि थाना परिसर में आने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ संवेदनशील, विनम्र एवं

किसानों को समय पर मिल रहे खाद बीज, खेती को मिली रफ्तार गरियाबंद। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही वितरण व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाते हुए टोकन प्रणाली समाप्त कर आवश्यकतानुसार एकमुश्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों का समय बच रहा है तथा उन्हें बार-बार समिति के चक्र नहीं लगाने पड़ रहे हैं। शासन द्वारा सभी सहकारी समितियों में खाद एवं बीज का नियमित भंडारण, उपलब्धता की सतत निगरानी तथा मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि खरीफ की बुवाई समय पर पूरी हो सके। किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अजय यादव को आईजी नियुक्त होने पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने दी बधाई



सेवाएं दी हैं। इसके बाद वे सरगुजा रेंज के आईजी, रायपुर रेंज के आईजी, आईजी (इंटेलिजेंस) तथा बिलासपुर रेंज के आईजी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय, रायपुर में पदस्थ रहने के उपरान्त उन्हें राजनांदगाँव रेंज का आईजी नियुक्त किया गया है। उनके

सरायपाली। यादव समाज के गौरव छत्तीसगढ़ कैडर के वर्ष 2004 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अजय यादव को राजनांदगाँव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त किए जाने एवं पदभार ग्रहण करने पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के पदाधिकारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। यादव ने अपने पुलिस सेवा काल में विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी एवं सशक्त कार्य किया है। वे मेनकुल पुलिसिंग में महारथ हासिल है कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय वीरता पदक तथा सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अजय यादव ने पुलिस अधीक्षक के रूप में नारायणपुर, कांकेर, बिलासपुर, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, दुर्ग तथा रायपुर सहित विभिन्न जिलों में अपनी

पदभार ग्रहण करने पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय सचिव इंजी. एस.डी. यादव, प्रदेश अध्यक्ष भूनेश्वर यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी नरेन्द्र कुमार यादव, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ममता यादव, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव नारद यादव (बेमेतरा), जितेंद्र यादव (बिलासपुर), धनेश यादव (ब्लॉक अध्यक्ष, बिलाईगढ़, जिला सारांगढ़-बिलाईगढ़), राजेंद्र यादव (जिला अध्यक्ष, सारांगढ़), विनोद यादव (जिला अध्यक्ष, महासमुंद), कार्यकारी जिला अध्यक्ष डॉ. पवन यादव, दिनेश कुमार यादव, राजेंद्र कुमार यादव (राजू), मयंक यादव, तुषार यादव (सरायपाली) तथा आर.के. यादव, महेश यादव, अनिल यादव (जिला अध्यक्ष, रायपुर), नागेश यादव एवं चन्दन यादव सहित अनेक पदाधिकारियों ने उन्हें उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं।

संपर्क केंद्र की तत्परता से महाराष्ट्र में बिछड़े 15 वर्षीय बालक सकुशल परिवार से मिला



बलौदाबाजार-भाटापारा। संचालित जिला संपर्क केंद्र की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय से महाराष्ट्र में अपने परिवार से बिछड़ा 15 वर्षीय बालक सलिक राम चक्र सकुशल अपने माता-पिता से मिल गया। बालक के सुरक्षित घर लौटने पर परिवार की खुशियां लौट आईं और भावुक माता-पिता ने जिला प्रशासन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गिन्दोला, तहसील लवन निवासी दुलेश घुव अपने परिवार सहित वर्तमान में कामठी (महाराष्ट्र) में मजदूरी कार्य करते हैं। इसी दौरान उनका 15 वर्षीय पुत्र सलिकराम घुव अचानक परिवार से बिछड़ गया। कामठी थाना क्षेत्र में अकेले घूमते हुए पाए जाने पर स्थानीय पुलिस ने बालक को संरक्षण में लिया और उससे पुछताछ कर उसके परिजनों के संबंध में जानकारी जुटाई। जानकारी के आधार पर कामठी पुलिस ने बलौदाबाजार-भाटापारा

जिले में संचालित संपर्क केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 9201899925 पर संपर्क कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही संपर्क केंद्र की टीम ने तत्काल सक्रिय होकर संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया तथा ग्राम गिन्दोला पहुंचकर बालक के परिजनों की प्रामाणिकता का सत्यापन कराया। इसके बाद सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं एवं कार्रवाई पूरी कर बालक सलिकराम घुव को सुरक्षित उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया। कई दिनों बाद अपने बेटे को सकुशल सामने देखकर माता-पिता की आंखें खुशी से नम हो गईं। उन्होंने जिला प्रशासन की संवेदनशील कार्यप्रणाली, संपर्क केंद्र की तत्परता तथा कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में किए गए मानवीय प्रयासों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की सक्रियता के कारण उनका बिछड़ा हुआ बेटा सुरक्षित वापस मिल सका।

कलेक्टर उड़के ने स्लिट लैप आई टेस्टिंग मशीन का किया शुभारंभ



गरियाबंद। जिला चिकित्सालय में कलेक्टर बीएस उड़के की उपस्थिति में आधुनिक स्लिट लैप आई टेस्टिंग मशीन का शुभारंभ किया गया। यह अत्याधुनिक मशीन आईडीबीआई बैंक द्वारा अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत जिला चिकित्सालय को प्रदान की गई है। इस मशीन के स्थापित होने से जिले के मरीजों को नेत्र परीक्षण की बेहतर एवं आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी तथा गंभीर नेत्र रोगों की समय रहते पहचान और उपचार में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर कलेक्टर बीएस उड़के ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आईडीबीआई बैंक ने जिले के मरीजों को ध्यान में रखते हुए स्वरेणणा से जिला चिकित्सालय को यह आधुनिक

मशीन उपलब्ध कराई है, जो सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीक से युक्त इस मशीन के माध्यम से जिले के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की नेत्र जांच सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। कलेक्टर उड़के ने स्वयं स्लीट लैप मशीन से अपनी आंखों की जांच कराकर मशीन का शुभारंभ किया तथा इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी भी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. टीसी पात्रा ने स्लीट लैप मशीन की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अत्याधुनिक आई टेस्टिंग मशीन है। जिसके माध्यम से आंख के बाहरी भाग, कॉर्निया, लेंस, रेटिना तथा आंख

की अन्य सूक्ष्म संरचनाओं की विस्तृत एवं सटीक जांच की जा सकती है। इस मशीन से आंखों के बारीक से बारीक रोगों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाया जा सकता है, जिससे समय पर उपचार संभव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि यह उपकरण नेत्र शल्य चिकित्सा से पहले और बाद की जांच के साथ-साथ ऑपरेशन थियेटर में भी काम आएगा। आईडीबीआई बैंक भिलाई के क्षेत्रीय प्रबंधक अकृल्य कल्याण ने कहा कि बैंक अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत जनहित एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय को स्लीट लैप आई टेस्टिंग मशीन उपलब्ध कराना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस आधुनिक मशीन से मरीजों को बेहतर नेत्र जांच की सुविधा मिलेगी तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। उन्होंने भविष्य में भी जनकल्याणकारी कार्यों में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग जारी रखने की बात कही। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यूएस नवरत्न ने बताया कि इस आधुनिक मशीन के उपलब्ध होने से जिला चिकित्सालय की नेत्र चिकित्सा सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। मरीजों की सटीक जांच, शीघ्र रोग पहचान एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने में यह मशीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही गंभीर मामलों को समय रहते चिन्हित कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

महावीर इंटरनेशनल संस्था के स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

धमतरी। डॉक्टर डे और सीए डे का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें डॉक्टर यश भोमराज छत्रेड़ और सीए हर्ष निलेश पाख का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महावीर वीरा गुप की महिलाओं का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर वीरा नीलू लुणावत, वीरा मधु बैद, वीरा अनीता कुकरेजा, वीरा शोभा बैद, वीरा अनीता लुणावत, वीरा मोना शाह, वीरा कल्पना लुणावत आदि उपस्थित थे। महावीर इंटरनेशनल वीरा शाखा द्वारा नवजात शिशुओं के लिए बेबी किट का वितरण भी किया गया। महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र धमतरी द्वारा संस्था के स्थापना दिवस



के उपलक्ष्य में तृतीय सोपान जिसमें संस्था की महत्वाकांक्षी वास्तव्य योजना शासकीय जिला अस्पताल में 50 नवजात शिशु को बेबी किट का वितरण किया गया। इसमें निम्न सदस्यों की उपस्थिति रही, उपाध्यक्ष वीरा अनीता कुकरेजा, सचिव वीरा मधु बैद, कोषाध्यक्ष वीरा अनीता

लूनावत, वीरा शोभा बैद, सहसचिव वीरा सजु बड़जात्या आदि सदस्य उपस्थित थे। संस्था की शीर्ष केंद्र द्वारा नवजात शिशुओं को संक्रमण से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

सीएम हेल्पलाइन बनी उम्मीद की नई राह, व्हीलचेयर मिलने से पटरी पर लौटी नूतन की जिंदगी

बलौदाबाजार। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू किये गये सीएम हेल्पलाइन 1076 से लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन से दिव्यांग नूतन कुमार रजक को व्हीलचेयर मिला जिससे उसके कई कार्य आसान हो गया। ग्राम अर्जुनी स्थित बजरंग चौक सीतला मंदिर के पास रहने वाले 32 वर्षीय नूतन कुमार रजक का जीवन वर्ष 2025 में एक सड़क दुर्घटना के बाद पूरी तरह बदल गया। हादसा इतना गंभीर था कि उनके दोनों पैर काटने पड़े। इस घटना ने न केवल उनकी शारीरिक क्षमता छीन ली, बल्कि घर से लगे छेदे से जनरल स्टोर तक पहुंचना भी उनके लिए बेहद कठिन हो गया। रोमर्रा के छेदे-छेदे काम भी दूसरों की मदद के बिना



संभव नहीं रह गए। ऐसे कठिन समय में एक दिन उन्होंने समाचार पत्र में सीएम हेल्पलाइन के बारे में पढ़ा। उनके मन में उम्मीद जगी कि शायद उनकी समस्या का भी समाधान इस माध्यम से हो सके। उन्होंने बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क किया। वहां उनकी बात गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनी गई तथा उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला।

इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज एक सप्ताह के भीतर उन्हें व्हीलचेयर उपलब्ध करा दी। व्हीलचेयर मिलने से अब नूतन कुमार रजक के लिए अपने जनरल स्टोर तक पहुंचना आसान हो गया है और वे फिर से आत्मविश्वास के साथ अपना काम सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सहायता उनके लिए केवल एक व्हीलचेयर नहीं, बल्कि नई जिंदगी और आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला एक प्रभावी और भरोसेमंद माध्यम बन गया है, जिसने उनके जीवन में फिर से उम्मीद की रोशनी जगा दी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये की दावा राशि का चेक प्रदान किया गया

गरियाबंद। कलेक्टर बीएस उड़के ने अपने कार्यालय कक्ष में गरियाबंद विकासखंड के ग्राम धवलपुर निवासी दिवंगत नितेश साहू की नामांकित हितग्राही सोमा साहू को 02 लाख रुपये की दावा राशि का चेक सौंपा। भारत सरकार की जनकल्याणकारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ बडौदा शाखा गरियाबंद द्वारा चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक ए.एम. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। जिसके तहत मात्र 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि दिवंगत नितेश साहू ने बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गरियाबंद के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना पंजीयन कराया था। उनके आकस्मिक निधन के उपरान्त योजना के प्रावधानों के अनुसार उनकी नामांकित सदस्य सोमा साहू को दो लाख रुपये की बीमा दावा राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई। कलेक्टर बीएस उड़के ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि जरूरत के समय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।

पीओपी निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियां हो प्रतिबंधित : हिंदू जागरण मंच

धमतरी। हिन्दू जागरण मंच जिला धमतरी ने सनातनी परम्पराओं से ही गणेश जी की प्रतिमा निर्माण हेतु मूर्तिकार संघ एवं कुहार समाज के आग्रह पर कलेक्टर धमतरी, जिला अनुविभागीय अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक धमतरी के नाम पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में कहा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियों के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध तथा पालन सुनिश्चित करने तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु आवेदन किया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों के निर्माण, विक्रय एवं विनिर्जन से जल प्रदूषण तथा पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँचती है। इसी उद्देश्य से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय



हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में प्राकृतिक मिट्टी एवं पर्यावरण-अनुकूल सामग्री से मूर्तियाँ बनाने पर बल दिया गया है। अतः निम्नलिखित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही किए जाने की मांग की है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, धारा 3 पर्यावरण संरक्षण हेतु केंद्र सरकार की शक्तियाँ। धारा 5 पर्यावरण संरक्षण हेतु निर्देश जारी

करने की शक्ति, धारा 15 अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत जारी आदेशों/निर्देशों के उल्लंघन पर दंड। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण रोकने एवं जल स्रोतों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान।

जोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी तथा पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों के निर्माण संबंधी दिशा-निर्देश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित पर्यावरण संरक्षण संबंधी आदेशों का पालन। हिंदू जागरण मंच ने कहा कि जिले में पीओपी की मूर्तियों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय की जांच कराई जाए तथा यदि कोई व्यक्ति या संस्था लागू आदेशों एवं पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएँ, तो उनके विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 तथा अन्य लागू विधि प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर पुरुषोत्तम निषाद जिला संयोजक, डेकिश्वर साहू, प्रान्त युवा आथाम प्रमुख एवं कार्यकारिणी सदस्य, हिन्दू जागरण मंच, छत्तीसगढ़ ने सूचना सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

महापौर के प्रयासों से पुल-पुलिया निर्माण के लिए राशि स्वीकृत

धमतरी। बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। महापौर जगदीश रामू रोहरा के सतत प्रयासों से सेमरा भी, कोड़ेगांव, डेमरटुकर, मोंगराहन एवं सेहराखबरी में पुल-पुलिया निर्माण कार्यों के लिए 44 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से बरसात के दौरान संपर्क मार्ग बाधित होने की समस्या दूर होगी तथा हजारों ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। महापौर रामू रोहरा ने इन बाढ़ प्रभावित गांवों की समस्या को लगातार शासन के समक्ष प्रमूखता से उठाया और ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए निरंतर



प्रयास किए। उनके जनहितकारी प्रयासों और सकारात्मक पहल के परिणामस्वरूप शासन द्वारा यह महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि से क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों का पुनर्निर्माण तथा आवश्यक स्थानों पर नई पुल-पुलियों का निर्माण कराया जाएगा। इन

निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार तथा दैनिक आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में होने वाली परेशानियों से स्थायी राहत मिलेगी। विशेष रूप से बरसात के मौसम में गांवों का संपर्क टूटने की समस्या समाप्त होगी, जिससे विद्यार्थियों, किसानों, मरीजों और आम नागरिकों को सौधा लाभ मिलेगा। महापौर रामू रोहरा ने इस जनहितकारी स्वीकृति के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद रूप कुमारी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की है और इसी सोच के अनुरूप प्रदेशभर में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। महापौर रोहरा ने कहा कि धमतरी विधानसभा सहित नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। जनता की प्रत्येक आवश्यक मांग को शासन तक पहुंचाकर उसका शीघ्र समाधान कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भी क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिलेगी, जिससे धमतरी जिले के विकास को नई गति और नई दिशा प्राप्त होगी।

सरकार का जोर व्यवस्था को सुधारने पर कम और दावों पर ज्यादा रहता है। यह बात भी छिपी नहीं है कि दिल्ली में जलभयव की समस्या पर सियासत भी खूब होती है।दिल्ली की एक प्रमुख सड़क पर भारी बारिश के बाद घुटनों तक जलभराव है। सड़क पर कारें, बसें, ऑटो-रिक्शा और मोटरसाइकिलें ट्रैफिक में फंसी हैं, जबकि एक व्यक्ति छाता लेकर पानी के बीच से गुजर रहा है। पृष्ठभूमि में आधुनिक इमारतें, ओवरपास, घने काले

बादल और बारिश के बीच चमकती इमरजेंसी लाइटें दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव से प्रमुख सड़कें डूबीं। राजधानी की मानसूनी चूनीतियों को दर्शाते हुए घुटनों तक पानी में फंसे वाहन और आवागमन के लिए जूझते लोग। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते अमूमन यह माना जाता है कि दिल्ली में समूची व्यवस्था अन्य शहरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगी। सरकार और स्थानीय प्रशासन के दावों में भी यही झलकता

पहली ही बारिश में थम गई दिल्ली, आखिर हर साल क्यों दोहराती है वही कहानी?

है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जब हकीकत सामने आती है, तब भी उसमें सुधार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है।इसका एक प्रमुख उदाहरण है बारिश के दिनों में दिल्ली की रफतार थम जाना। हर साल राजधानी के बाशिंदों को जलभराव और यातायात अवरुद्ध हो जाने की वजह से दिक्कों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में समग्र विकास के आश्वासनों के साथ सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन समस्याओं का संजाल अभी भी

कमोबेश वैसा ही बना हुआ है।यही वजह है कि बीते गुरुवार को मानसून की पहली तेज बारिश में ही कई जगह सड़कें तालाब बन गईं, यातायात ठप हो गया और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। सवाल है कि बरसात से पहले संबंधित महकमों की ओर से जिन पूर्व तैयारियों का भरोसा दिलाया जाता है, वे समय आने पर कहाँ गायब हो जाती हैं।कहने को राष्ट्रीय राजधानी में हर साल मानसून के आगमन से काफी पहले समस्याओं से निपटने

की औपचारिक तैयारी शुरू हो जाती है। इसके तहत मुख्य रूप से छोटे-बड़े नालों और सड़क किनारे जलनिकासी के लिए बनी नालियों का सफाई करनी होती है। मगर इन तैयारियों का अधिकांश कार्य कागजों तक ही सीमित रहता है। जाहिर है कि सरकार का जोर व्यवस्था को सुधारने पर कम और दावों पर ज्यादा रहता है। यह बात भी छिपी नहीं है कि दिल्ली में जलभराव की समस्या पर सियासत भी खूब होती है।

इस बार भी सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के मुकाबले जलभराव का संकट काफी कम हुआ है। वहीं, विपक्ष का कहना है कि दो-तीन चिह्नित स्थलों को छोड़कर बाकी जगह का हाल जस का तस बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार तुलनात्मक सुधार का हवाला देकर अपनी पीठ थपथपाने के बजाय समस्या की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करे और

कत्रिम मेधा के दौर में शिक्षा, मौलिक चिंतन और मानवीय विवेक की सबसे बड़ी चुनौती

(अतुल अग्रवाल)

शिक्षा का सबसे जीवंत पक्ष मनुष्य के बीच का संवाद है, जिसे कोई ‘एल्गोरिथ्म’ प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसलिए एआई को शिक्षक का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी मानना ही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होगा। एक विद्यार्थी और एआई रोबोट के बीच संतुलन का प्रतीकात्मक दृश्य, जो शिक्षा में कृत्रिम मेधा और मानवीय विवेक के संबंध को दर्शाता है।

शिक्षा में कृत्रिम मेधा (एआई) के बढ़ते प्रभाव के बीच मानवीय विवेक, मौलिक चिंतन और नैतिक निर्णय क्षमता के महत्व को दर्शाती प्रतीकात्मक फीचर इमेज।

पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम मेधा यानी एआई ने जिस तेजी से दुनिया को बदला है, उसने औद्योगिक और इंटरनेट क्रांति की स्मृतियों को ताजा कर दिया है। कभी कल्पित विज्ञान का विषय मानी जाने वाली यह तकनीक आज हमारे मोबाइल फोन, कार्यालयों, अस्पतालों, न्यायालयों और विद्यालयों तक पहुंच चुकी है।

विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल जिस स्तर पर होने लगा है, उससे यह पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में कक्षाओं का स्वरूप, शिक्षण की पद्धति और सीखने की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं रहने वाली। मगर प्रत्येक तकनीकी क्रांति अपने साथ एक मूलभूत प्रश्न भी लेकर आती है - क्या हम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, या धीरे-धीरे तकनीक हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता को संचालित करने लगी है? यही सवाल आज शिक्षा जगत के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।

इसमें दो राय नहीं कि कृत्रिम मेधा ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज एक विद्यार्थी घर बैठे विश्वस्तरीय अध्ययन-सामग्री तक पहुंच सकता है। कठिन वैज्ञानिक आधारभारणओं को सरल भाषा में समझ सकता है, विदेशी भाषाएं सीख सकता है और अपनी कमजोरियों का विश्लेषण भी कर सकता है।

दूसरी ओर, शिक्षक भी एआई की सहायता से पाठन योजनाएं तैयार करने, विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने में समर्थ हो रहे हैं। यदि एआई का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, तो यह शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने का सशक्त माध्यम बन सकती है। मगर यहीं से इस परिवर्तन का दूसरा पक्ष भी सामने

आता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना अर्जित करना नहीं, बल्कि चिंतन, तर्क, विवेक और व्यक्तित्व का विकास करना है। यदि किसी विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में मिल जाए, तो क्या वह प्रश्नों से जुड़ने का धैर्य विकसित कर पाएगा? यदि निबंध, परियोजनाएं और शोध-कार्य कृत्रिम मेधा के भरोसे तैयार होने लगें, तो मौलिक चिंतन और सृजनात्मकता का भविष्य क्या होगा? दरअसल, शिक्षा की वास्तविक शक्ति उत्तर में नहीं, बल्कि उस बौद्धिक यात्रा में निहित होती है, जो उत्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति स्वयं तय करता है। यदि यह यात्रा समाप्त हो गई, तो शिक्षा केवल सूचना-संग्रह का माध्यम बनकर रह जाएगी। ऐसे में यह मान लेना कि एआई शिक्षक का स्थान ले सकती है, वास्तविकता से कोसों दूर है। एक मशीन तथ्यों का संकलन कर सकती है, मगर चरित्र का निर्माण नहीं। वह भाषा सिखा सकती है, मगर संवेदनशीलता नहीं। वह जानकारी दे सकती है, पर प्रेरणा नहीं। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ता, बल्कि विद्यार्थी के भीतर जिज्ञासा, आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक दृष्टि का विकास भी करता है। शिक्षा का सबसे जीवंत पक्ष मनुष्य के बीच का संवाद है, जिसे कोई ‘एल्गोरिथ्म’ प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इसलिए एआई को शिक्षक का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी मानना ही विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होगा। हालाँकि, चुनौती केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कृत्रिम मेधा का विस्तार शिक्षा में एक नई सामाजिक असमानता को भी जन्म दे सकता है। महानगरों के विद्यार्थियों के पास उच्च गति का इंटरनेट, आधुनिक उपकरण और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि देश के अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का अभाव है। यदि भविष्य की शिक्षा एआई पर आधारित होगी और तकनीकी संसाधनों तक पहुंच असमान बनी रहेगी, तो यह अंतर केवल डिजिटल नहीं रहेगा, बल्कि यह अवसरों, रोजगार और सामाजिक प्रगति के बीच गहरी खाई में बदल सकता है। इसलिए एआई के युग में डिजिटल सभानता केवल तकनीकी नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी विषय है। एक गंभीर चिंता उभर रही है डेटा की सुरक्षा एवं निजता की। एआई आधारित मल विद्यार्थियों की अध्ययन-शैली, व्यवहार, रुचियों और व्यक्तिगत जानकारी का विशाल भंडार तैयार कर रहे हैं।

जंगलों से गुम होती महुआ की विरासत, बदलती खेती और सड़क चौड़ीकरण ने बढ़ाई चिंता

(आदित्य कुमार यादव)

गर्मी की शुरुआत में जब खेतों में काम कम हो जाता है, तब महुआ के फूल आजीविका का सहारा बनते हैं। सुबह-सुबह कई महिलाएं और बुजुर्ग टोकरियां लेकर इन फूलों को बीनने निकलते हैं। मध्य भारत के जंगलों में पिछले कई वर्षों के अनुभव बताते हैं कि महुआ के वृक्ष धीरे-धीरे बदल रहे हैं, लेकिन यह बदलाव अक्सर आँकड़ों और दस्तावेजों से ओझल रह जाता है। वन से जुड़े विशेषज्ञ जागीर, बलिया और जौनपुर जैसी जिलों में जैसे बारीकी से महसूस करते रहे हैं। गांवों की अर्थव्यवस्था में महुआ सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि एक जीवनरेखा है, खासकर उन परिवारों के लिए जो जंगलों पर निर्भर हैं।

गर्मी की शुरुआत में जब खेतों में काम कम हो जाता है, तब महुआ के फूल आजीविका का सहारा बनते हैं। सुबह-सुबह कई महिलाएं और बुजुर्ग टोकरियां लेकर इन फूलों को बीनने निकलते हैं। इसके बीजों से निकलने वाला तेल रसोई और औषधि का हिस्सा होता है, जबकि महुआ के पेड़ की चनी छांव पशुओं के लिए आराम की जगह बनाती है, लेकिन अब यह मौसमी दृश्य धीरे-धीरे कम होता दिख रहा है।

महुआ केवल एक वन वृक्ष नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शुष्क वन पारिस्थितिकी का आधार है। इसके फूल भोजन, पेय और पशु चारे के रूप में उपयोग होते हैं, जबकि बीजों से निकला तेल खाद्य, औषधीय और घरेलू उपयोग में आता है। इसकी पत्तियां पारंपरिक पत्तल-दोने बनाने में काम आती हैं और घनी पत्तियां गर्मी में पशुओं तथा वन्यजीवों को छाया प्रदान करती हैं। कृषि के सुख मौसम में इसके फूल मधुमक्खियों जैसे परागहणकों के लिए भी भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं।

महुआ की अहमियत केवल इसके प्रत्यक्ष उपयोगों तक सीमित नहीं है। यह शुष्क वनों की पारिस्थितिकी, स्थानीय जैव विविधता और वन-आधारित आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनेक आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए यह केवल आय का स्रोत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं, स्थानीय ज्ञान और खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ वृक्ष है। इसलिए महुआ का संरक्षण केवल एक प्रजाति को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि उससे जुड़े पूरे सामाजिक और पारिस्थितिकी तंत्र को



सुरक्षित रखने का सवाल है।

क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है कि महुआ के पुराने पेड़ तो अब भी दिख जाते हैं, लेकिन नए पौधे लगभग नदारद हैं। अनेक क्षेत्रों में मौजूद ये परिपक्व वृक्ष अपनी प्राकृतिक आयु के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं, जबकि उनका प्राकृतिक पुनरुत्पादन सीमित रह गया है। कई बीजारोपण सफल नहीं हो पाते और लंबी शुष्क अवधियों, भूमि-विघटन, अत्यधिक चराई तथा मिट्टी के सख्त होने के कारण पौधे मुरझा जाते हैं। यहाँ तक कि फूल बीनने के दौरान साफ-सफाई के लिए लगाई गई मौसमी आग भी, यदि नियंत्रित न हो, तो बीजों के फैलाव और नए पौधों के स्थापित होने में बाधा बनती है। परिणामस्वरूप, पुराने महुआ वृक्ष तो अब भी घने छत्रों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जगह लेने वाली नई पीढ़ी पर्याप्त संख्या में विकसित नहीं हो पा रही।

महुआ एक कठोर प्रजाति का वृक्ष है, जो गर्मी और सूखे का सामना कर सकती है, लेकिन अब वर्षा में जो बदलाव आ रहे हैं, वे इस पर भारी पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का अनुभव है कि महुआ के फूलों का मौसम अब पहले जैसा अनुमानित नहीं रहा। देरी से पड़ने वाली सर्दियों की बारिश और लंबी सूखा अवधियों ने फूलों को या तो कम कर दिया है या फिर उनके खिलने का समय ही बदल गया है। नतीजतन, फूल बीनने वाले परिवारों के लिए यह मौसम पहले जितना भरोसेमंद नहीं रह गया है।

यह दबाव केवल जंगलों तक सीमित नहीं है। 'नेचर सर्वटेनेबिलिटी' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत के कृषि परिदृश्यों में बिखरे हुए बड़े पेड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2010-11 में मौजूद बड़े कृषि-वृक्षों में लगभग 11.2 प्रतिशत वृक्ष 2018 तक गायब हो चुके थे। इसके बाद 2018 से 2022 के बीच 50 लाख से अधिक बड़े वृक्ष और लुप्त हो गए। इसे शोथकर्ताओं ने बदलती कृषि पद्धतियों से जोड़कर देखा है। ग्रामीण विकास के तहत सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान महुआ के सैकड़ों पुराने पेड़ उखाड़ दिए गए, जो दशकों से ग्रामीण सड़कों की शोभा बढ़ा रहे थे।

इससे भी चिंताजनक सांस्कृतिक अंतराल है। एक समय था जब गांव के चौपालों, चरगाहों और खेतों की मेड़ों पर महुआ के पेड़ दिखाई देते थे। इसकी पत्तियों से पत्तल बनाई जाती थी, जो सामुदायिक भोज और शादियों का अभिन्न हिस्सा थीं। मगर अब प्लास्टिक की प्लेटों ने पत्तलों की जगह ले ली है, जिससे एक ओर आजीविका प्रभावित हुई है, तो दूसरी ओर महुआ की सांस्कृतिक पहचान भी फोकी पड़ गई है। बुजुर्ग अब भी याद करते हैं कि कैसे एक पीढ़ी पहले खेतों के किनारे महुआ के वृक्षों की कतारें होती थीं, जो अब नजर नहीं आतीं।

कुछ राज्यों में संगठित खरीद और मूल्य-वर्धन योजनाओं से महुआ संरक्ष करने वालों को लाभ तो हुआ है, लेकिन प्रसंस्करण और

बाजार तक सीमित पहुंच के कारण इसकी आर्थिक क्षमता का पूरा लाभ स्थानीय समुदायों तक नहीं पहुंच पाया है। क्षेत्रीय अनुभव बताते हैं कि बहुत से सरल उपाय महुआ के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। उन क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, जहां यह प्रजाति आम है, साथ ही पेड़ों की आयु संरचना और बीजों की जीवित रहने की दर पर नजर रखना आवश्यक है। गांव के स्तर पर फूल बीनने के मौसम में जमौन पर आग लगाने पर नियंत्रण जरूरी है। इससे विशेष रूप से मानसून के शुरुआती महीनों में, जब नए पौधे निकलते हैं, तब इनके जीवित रहने की दर में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

सबसे अहम है सामुदायिक भागीदारी। जब लोगों को समझाया जाता है कि पौधों की रक्षा करना क्यों जरूरी है, तो वे इसे अपना लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज के पौधारोपण अभियानों में अक्सर तेजी से बढ़ने वाली या फल देने वाली प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाती है। महुआ के पौधे शायद ही मांगे जाते हैं, जिससे स्थानीय नर्सरियों में इनकी उपलब्धता न के बराबर हो जाती है। दो मत नहीं कि सरकारी नर्सरियों में महुआ को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। महुआ के क्षरण के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। जलवायु परिवर्तन से फूल आने के समय में बदलाव, अत्यधिक चराई, अनियंत्रित मौसमी आग, भूमि-विघटन, सड़क चौड़ीकरण, कृषि पद्धतियों में परिवर्तन तथा महुआ पौधों के सीमित रोपण जैसे अनेक कारक मिलकर इसकी नई पीढ़ी को कमजोर कर रहे हैं। सहायक प्राकृतिक पुनरुद्धार, क्षीण हिस्सों में संवर्धन रोपण और कृषि-वानिकी प्रणालियों में महुआ को शामिल करने से मौजूदा पेड़ों पर दबाव कम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में सौ वर्ष से अधिक पुराने विरासत वृक्षों के रखरखाव की जो पहल शुरू हुई है, वह वास्तव में महुआ संरक्षण के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। पारिस्थितिकीय गिरावट कभी नाटकीय रूप से नहीं होती। पेड़ अचानक नहीं मिटते। वे धीरे-धीरे ढल जाते हैं, जब उनकी अगली पीढ़ी लड़खड़ाने लगती है। इसलिए महुआ के भविष्य की सुरक्षा न केवल एक पारिस्थितिकीय चुनौती है, बल्कि आजीविका का सवाल भी है। यदि समय रहते निगरानी, सामुदायिक सहयोग और संस्थागत समर्थन मिल जाए, तो यह अनमोल वृक्ष भारत के सूखे जंगलों में फिर से पनप सकता है।

3 देशों से भारत के लिए आखिर क्या लाए मोदी?

(नीरज कुमार दुबे)

मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा इसलिए भी खास रही क्योंकि करीब 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक माओरी रीति से स्वागत किया गया और उसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ लंबी बातचीत हुई। करीब एक सप्ताह के विदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वदेश लौट रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वह केवल तीन देशों की यात्रा पूरी करके लौटे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वह दुनिया के सामने नए भारत की ताकत, उसकी बढ़ती हैसियत और उसके उज्ज्वल भविष्य का दमदार परिचय देकर लौटे हैं। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान मोदी ने तीनों देशों के साथ रक्षा, व्यापार, शिक्षा, ऊर्जा, तकनीक और समुद्री सुरक्षा जैसे कई अहम समझौते किए। साथ ही उन्होंने दुनिया को यह भी बताया कि आज का भारत सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपनी मिसाइलों की ताकत, आधुनिक तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के संकल्प के दम पर नई ऊंचाइयों और तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही तीनों देशों में प्रधानमंत्री का जिस गर्मजोशी और भव्य अंदाज में स्वागत हुआ, उसने भारत की बढ़ती साख की साफ तस्वीर पेश की। इतना ही नहीं, जब मोदी ने वहां बसे भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो वहां के शीर्ष नेताओं ने भी उनकी लोकप्रियता और भारतीयों के उत्साह को करीब से देखा। इससे एक बार फिर साफ हो गया कि मोदी की पहचान अब केवल भारत के प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं

है, बल्कि दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में उनकी छवि लगातार और मजबूत होती जा रही है।

न्यूजीलैंड – सबसे पहले बात न्यूजीलैंड की। यह यात्रा इसलिए भी खास रही क्योंकि करीब 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक माओरी रीति से स्वागत किया गया और उसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ लंबी बातचीत हुई। इस मुलाकात का सबसे बड़ा फैसला दोनों देशों के रिशतों को नई रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाना रहा। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच कारोबार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने पर भी सहमति जताई ताकि दोनों देशों के व्यापारियों और उद्योगों को सीधा लाभ मिल सके।

न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर कई बड़े कदम उठाए गए। दोनों देशों की नौसेनाएं अब जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की रसद सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। समुद्र से जुड़ी जानकारीयों साझा होंगी, संयुक्त अभ्यास बढ़ेंगे और समुद्री सुरक्षा पर हर साल नियमित बातचीत होगी। आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्य समूह बनाने का भी फैसला हुआ जिससे दोनों देश जानकारी साझा कर आतंक के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा भूकंप, सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ेगा। डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में न्यूजीलैंड की आधुनिक तकनीक भारत तक पहुंचेगी। पर्यटन,

खेल, संस्कृति, समुद्री विरासत, खाद्य तकनीक और समुद्री अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी कई समझौते हुए। नागालैंड और उत्तराखंड में कीवी फल के लिए दो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को बेहतर तकनीक और अधिक उत्पादन का लाभ मिल सके। न्यूजीलैंड ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने का भी फैसला किया। अंटार्कटिका अनुसंधान, खाद्य तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच नए सहयोग का रास्ता खुला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए न्यूजीलैंड ने अपना समर्थन दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी दोनों देश एकमत दिखाई दिए।

ऑस्ट्रेलिया – अब बात ऑस्ट्रेलिया की। मेलबर्न में हुई वार्षिक शिखर बैठक के दौरान दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती दी। नई संयुक्त रक्षा घोषणा के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, नई तकनीक और समुद्री कानूनों के पालन पर साथ काम करने का फैसला हुआ। समुद्री सुरक्षा के लिए अलग कार्ययोजना बनी और दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच भी नया समझौता हुआ।ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों ने साथ मिलकर काम करने का भरोसा दोहराया। लंबे समय से लंबित असेन्य परमाणु समझौते को पूरी तरह लागू करने का रास्ता साफ हुआ, जिससे भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति आसान होगी। नई तकनीक, साइबर सुरक्षा और जरूरी आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी नई साझेदारी बनी।शिक्षा और कौशल विकास में भी

कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। खनन क्षेत्र के लिए भूवनेश्वर में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलेंगे जिससे भारतीय छात्रों को विदेश जाए बिना बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। दोनों देशों के कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के बीच भी सहयोग बढ़ेगा। इस यात्रा की एक खास उपलब्धि भारत की प्राचीन धरोहरों की वापसी भी रही। नंदी, भगवान कार्तिकेय और मां काली से जुड़ी तीन दुर्लभ प्राचीन मूर्तियां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटाने का फैसला किया। इसके अलावा सौर ऊर्जा, विज्ञान, फिल्म निर्माण, पारंपरिक ज्ञान, खनिज खोज और औषधि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भी कई नए समझौते हुए।

इंडोनेशिया – प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की शुरुआत इंडोनेशिया से हुई जहां दोनों देशों ने अपने पुराने रिशतों को और मजबूत बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई बातचीत में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, अंतरिक्ष, ऊर्जा, शिक्षा और संस्कृति जैसे लगभग हर क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने का फैसला किया।

ब्रस्मोस मिसाइल प्रणाली और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर सहयोग बढ़ेगा। समुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास, तटरक्षक बलों के बीच तालमेल और जहाज निर्माण में भी साथ काम होगा। भारत और इंडोनेशिया आतंकवाद के खिलाफ भी मिलकर काम करेंगे और नई तकनीक का गलत इस्तेमाल रोकने पर भी सहयोग बढ़ेगा। व्यापार बढ़ाने, दुर्लभ खनिजों की

आपूर्ति मजबूत करने, इस्पात उद्योग में संयुक्त निवेश करने और दोनों देशों की मुद्राओं में लेन-देन बढ़ाने पर भी सहमति बनी। स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाइयों के मानकों, चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण और खाद्य सुरक्षा पर समझौते हुए। कृषि, उर्वरक, ऊर्जा, दूरसंचार, विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और आपदा प्रबंधन में भी नए समझौते हुए।

दोनों देशों ने समुद्री और हवाई संपर्क बढ़ाने, सबांग बंदरगाह के विकास में सहयोग, डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने और छोटे कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने की दिशा में भी कदम बढ़ाया। साथ ही सांस्कृतिक रिशतों को मजबूत करने के लिए प्रंबानन मंदिर के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा और दोनों देशों ने अगले दो वर्षों को गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर और की हजर देवतारा की सांस्कृतिक स्मृति के रूप में मनाने का फैसला भी किया। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी का यह तीन देशों का दौरा कई मायनों में सफल माना जा सकता है। न्यूजीलैंड के साथ ऐतिहासिक नई साझेदारी बनी, ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा, शिक्षा और ऊर्जा संबंधों को नई मजबूती मिली, जबकि इंडोनेशिया के साथ समुद्री सुरक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग का नया रास्ता खुला। इन समझौतों का असर आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और रोजगार जैसे कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि इस पूरे दौरे को भारत की विदेश नीति के लिए एक मजबूत और दूरगामी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

सुकमा के छात्र नीट और आईआईटी में बना रहे पहचान, शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदल रही जिले की तस्वीर

भव्य शाला प्रवेशोत्सव में बच्चों का हुआ आत्मीय स्वागत

तिलक लगाकर किया स्वागत, छात्राओं को मिली साइकिल, बच्चों को बांटे गए बैग, पुस्तकें और गणवेश

सुकमा। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई। सुकमा जिले में शबरी ऑडिटोरियम में आयोजित जिलास्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में नवप्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडवी ने की। इस अवसर पर शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सुकमा के सुदूर क्षेत्रों के विद्यार्थी भी अब अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर नीट (हृदयधड़) और आईआईटी (दुहड़) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडवी ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज सुकमा तेजी से बदल रहा है और शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि हर माता-पिता का सपना है कि उनके बच्चे अच्छी



शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ें और समाज तथा देश की सेवा करें। कार्यक्रम में सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 30 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। वहीं प्रार्थमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल बैग, पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और आवश्यक स्टेशनरी सामग्री प्रदान की गई, ताकि संसाधनों की कमी

उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। इस अवसर पर कबाड़ से जुगाड़ विषय पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा देखने को मिली। कलेक्टर सुकमा श्री अमित कुमार ने कहा कि सुकमा के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी अब अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर नीट (हृदयधड़) और आईआईटी (दुहड़) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में

सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निःशुल्क कोचिंग, आधुनिक पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन की ओर से मुख्य अतिथि श्री रूप सिंह मंडवी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी.आर. मंडवी ने आभार व्यक्त करते हुए जिले में शिक्षा से जुड़ी सभी शासकीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंगमा सोयम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री महेश कुंजाम, नगर पालिका अध्यक्ष श्री हंगाराम मरकाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, अधिभावक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

गुलाब की खुशबू से महकी किसान विकास कुमार की किस्मत



जगदलपुर। पारंपरिक खेती से अलग हटकर अगर आधुनिक और वैज्ञानिक तौर-तरीकों को अपनाया जाए, तो कृषि क्षेत्र में कितनी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, इसका जीता-जागता उदाहरण पेश किया है कालीपुर ग्राम के प्रगतिशील किसान श्री विकास कुमार श्रीवास्तव ने। उन्होंने अपनी सृजनशील और कड़ी मेहनत से गुलाब की खेती को मुनाफे का एक शानदार जरिया बना दिया है। विकास कुमार श्रीवास्तव ने अपने 8000 वर्गमीटर के खेत में संरक्षित स्थिति में व्यावसायिक स्तर पर गुलाब की वैज्ञानिक खेती की शुरुआत की थी। सही समय पर सिंचाई, संतुलित पोषण प्रबंधन और उन्नत फसल संरक्षण उपायों के बदैलत उनकी फसल में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादकता देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने

अपने खेत से लगभग एक लाख 60 हजार गुलाब के डंठलों का बंपर उत्पादन प्राप्त किया। बाजार में इन गुलाबों की भारी मांग के चलते विकास कुमार को अपनी फसल का कुल बाजार मूल्य लगभग 8 लाख रुपये प्राप्त हुआ। यदि इस खेती के आर्थिक गणित को समझें, तो इसमें कुल 4 लाख 20 हजार रुपये की लागत आई थी, जिसे निकालने के बाद उन्हें 3 लाख 80 हजार रुपये का सीधा और शुद्ध मुनाफा

हासिल हुआ। यह उपलब्धि साबित करती है कि कम क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर उद्यमीकी फसलों से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। गुलाब की इस सफल खेती ने न केवल विकास कुमार श्रीवास्तव को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि आज वे आस-पास के क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी एक बड़े प्रेरणास्रोत और रोल मॉडल बन चुके हैं।

नव पदस्थ सीईओ श्री एम. भार्गव ने बस्तर मुन्ने शिविर का किया निरीक्षण

दुतेवाड़ा। जिले के नव पदस्थ जिला पंचायत सीईओ श्री एम. भार्गव ने ग्राम पंचायत मेटापाल क्रमांक-2 में आयोजित बस्तर मुन्ने शिविर का निरीक्षण कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया, ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा सेवा वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। सीईओ श्री भार्गव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस्तर मुन्ने शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने आधार कार्ड निर्माण एवं संशोधन, आयुष्मान कार्ड पंजीयन, श्रम कार्ड, जीब कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जाति प्रमाण पत्र तथा महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न सेवाओं में तेजी लाने और पात्र हितग्राहियों को बिना क्लिब लाभ पहुंचाने को कहा।

वन विभाग की पहल से आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिला स्वरोजगार का सहारा

17 लाख रुपये के ऋण से चार हितग्राहियों को मिला नया जीवन

बीजापुर। वन प्रबंधन समितियों के छातों में जमा लाभांश एवं चक्रीय निधि की राशि का उपयोग करते हुए वनमंडल बीजापुर ने आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं वनांचल के ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल की है। विभाग द्वारा कुल 17 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करारकर चार हितग्राहियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया गया है।



इस योजना के अंतर्गत पामेड़ एवं आवापल्ली परिक्षेत्र का चार हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। इनमें तीन हितग्राहियों को किसान दुकान संचालन हेतु क्रमशः 2 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख रुपये

तथा एक हितग्राही को ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं डेजर खरीदने के लिए 10 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। लाभान्वित हितग्राहियों में दिलीप बीराबोईन (कोतापल्ली समिति), दिनेश कुमार कचलम (मुरदोड़ समिति), श्रीमती जोशिला भगत (कोतापल्ली समिति) तथा

सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को भी बढ़ावा देना है। यह पहल विशेष रूप से आत्मसमर्पित नक्सलियों को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध करारकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, समाज में स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र में शांति, विश्वास और समावेशी विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वनमंडल बीजापुर ने भविष्य में भी पात्र हितग्राहियों को विभिन्न आजीविका आधारित योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही है। यह पहल वनांचल के ग्रामीणों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास एवं आर्थिक सशक्तिकरण का प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरी है।

ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ घंटों में जुड़ा राशन कार्ड में आवेदक की पुत्री का नाम

सेवा सेतु पोर्टल के जरिए एक ही दिन में हुआ निराकरण

कलेक्टर ने बसंत को सौंपा संशोधित राशन कार्ड

कांकेर। छत्तीसगढ़ शासन की जनहितकारी पहल सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और सुलभ सेवाएं प्रदाय कार्ड जा रही हैं। इसी क्रम में ग्राम तेलावट निवासी बसंत कुमार साहू ने अपनी तीन वर्षीय बेटी गेस्त्रीका का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए सेवा सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के अगले ही दिन उनकी बेटी का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया गया। राशन कार्ड की अद्यतन प्रति जिला कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर ने आवेदक साहू को अपने हाथों से प्रदान की। त्वरित कार्रवाई से प्रसन्न बसंत कुमार साहू ने



मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से अब सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं

लगाने पड़ते। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर कम समय में ही आवश्यक सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु पोर्टल

से आम नागरिकों का समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है तथा शासन की सेवाएं अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनी हैं।

विषय विशेषज्ञों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

उत्तर बस्तर कांकेर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ अंतर्गत नवनिर्गुप्त विषयवस्तु विशेषज्ञों का "बदलते परिदृश्य में कृषि विज्ञान केन्द्रों की कार्यप्रणाली" विषय पर ओरिएंटेशन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 जुलाई तक कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. गिरिश चट्टेल ने ऑनलाइन माध्यम से कहा कि विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि अनुसंधान एवं कृषक समुदाय के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी



है। विशेष रूप से बस्तर संभाग में पदस्थ नवनिर्गुप्त विषयवस्तु विशेषज्ञों से सम्पर्ण, नवाचार एवं सेवा भाव के साथ कार्य करते हुए किसानों तक उन्नत कृषि तकनीकों का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने की बात कही। इसके अलावा डॉ. एस.

आर. के. सिंह निदेशक ने कृषि विज्ञान केन्द्रों, राज्य कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए डिजिटल एवं ई-एक्सटेंशन माध्यमों के प्रभावी उपयोग की महत्ता बताई। कृषि विज्ञान केन्द्र के डॉ. बीरबल साहू ने बताया कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के कुल 33 विषय विशेषज्ञ सम्मिलित हुए।

राष्ट्रीय अजजा आयोग के विधिक सलाहकार ने वन-धन केन्द्र इच्छापुर का किया अवलोकन

उत्तर बस्तर कांकेर। भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के वरिष्ठ विधिक सलाहकार प्रकाश कुमार उर्फ के आज जिले के प्रवास के दौरान कांकेर विकासखंड के ग्राम इच्छापुर पहुंचे जहां उन्होंने वन-धन केन्द्र का अवलोकन कर समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने हरा प्रसंस्करण केन्द्र (प्रोसेसिंग यूनिट) में समूह की महिलाओं से चर्चा की तथा इससे होने वाली आय के बारे में पूछा। साथ ही और भी बेहतर ढंग से कार्य करने



की बात कही। इस अवसर पर उनके द्वारा प्रसंस्करण केन्द्र परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत पौधे भी रोपे गए। इस मौके पर उनके साथ आए

अजय कुमार चौबे, कुंवर जितेन्द्र सिंह राणा तथा सूर्यनारायण सूरि तथा डीएफओ कांकेर रौनक गोयल व वन विभाग का अमला मौजूद था।

पिपलावंड मारीपारा का आंगनबाड़ी केंद्र बना गुणवत्ता, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बस्तर में प्रारंभिक शिक्षा का नया मॉडल : आंगनबाड़ी बनी बच्चों के सपनों की पाठशाला

बस्तर। छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक बाल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बस्तर जिले के ग्राम पंचायत पिपलावंड के मारीपारा आंगनबाड़ी केंद्र ने एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मनरेगा और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से निर्मित यह आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र अब केवल बच्चों के पोषण और देखभाल का केंद्र नहीं, बल्कि आकर्षक, सुरक्षित और नवाचार आधारित प्रारंभिक शिक्षा का सशक्त माध्यम बन गया है। पहले जर्जर भवन में संचालित होने वाले इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पढ़ाई और गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ग्राम पंचायत की पहल पर जनपद पंचायत बस्तर के माध्यम से नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त की गई। वर्ष 2024-25 में कुल 11.69 लाख रुपये की लागत से भवन का निर्माण कराया गया, जिसमें मनरेगा से 8 लाख रुपये, महिला एवं बाल विकास विभाग से 2 लाख रुपये तथा गौड़ खनिज मद से 1.69 लाख रुपये की



राशि का उपयोग किया गया। नवीन भवन का बाहरी स्वरूप बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। भवन की दीवारों पर हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी अक्षर, आकर्षक चित्र, अलफ़बेट ट्री और शैक्षणिक चित्र चिह्न उकेरे गए हैं, जिससे

बच्चों में खेल-खेल में सीखने की रुचि विकसित हो रही है। आंगनबाड़ी के अंदर भी सीखने के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। सचित्र हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी अलफ़बेट, 1 से 100 तक की संख्या तालिका, बच्चों की

सामुदायिक सहभागिता का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान कर रही हैं और स्थानीय समुदाय भी केंद्र के संचालन एवं रखरखाव में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं।

जिला स्तरीय जन्म-मृत्यु अंतरविभागीय समन्वय की हुई बैठक, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देशों के बारे में कराया गया अवगत

दुतेवाड़ा। विगत दिवस जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय जन्म-मृत्यु अंतरविभागीय समन्वय की बैठक आयोजित किया गया था। बैठक में जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन के दिशा निर्देश के विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 27 नवंबर 2026 अधिसूचना के तहत ऐसी घटना जो 22 दिन से 30 दिन के भीतर के घटना की पंजीयन रजिस्ट्रार द्वारा की जाए तो 20 रुपये के क्लिब फ़ीस के भुगतान पर पंजीयन किया जायेगा। इसके अलावा ऐसी घटना जो 30 दिन से 1 वर्ष के भीतर घटना के पंजीयन की जानकारी रजिस्ट्रार को दी जाये तो 100 रुपये के क्लिब फ़ीस के भुगतान तथा 1 वर्ष के पश्चात् घटना के पंजीयन के लिए 100 रुपये के क्लिब फ़ीस का प्रावधान है। इसके साथ ही एक वर्ष पश्चात् रिकॉर्ड की खोज बीन

हेतु प्रत्येक वर्ष का 20 रुपये का शुल्क लिया जावेगा। प्रमाण पत्र ग़ुम हो जाने की स्थिति में द्वितीय प्रति जारी करने पर 50 रुपये का शुल्क लिया जावेगा। पूर्व में पंजीकृत जन्म, मृत्यु के मामले में जन्म, मृत्यु, नाम तिथि एवं स्थान में संशोधन नहीं किया जा सकता। जन्म के मामले में नाम (बच्चे, माता, पिता) संशोधन किया जा सकता है केवल विशेष परिस्थितियों जैसे लिपिकीय त्रुटि होने पर, जन्म के पश्चात् 5 वर्ष की आयु तक साथ (शाला प्रवेश आधार कार्ड, अन्य शासकीय दस्तावेज) के आधार पर किया जा सकता है। इसके अलावा मृत्यु के मामले में नाम (मृतक, माता, पिता) संशोधन नहीं किया जा सकता है परन्तु केवल लिपिकीय त्रुटि होने पर तथा मृत्यु पंजीयन के पूर्व शासकीय अभिलेख जिसमें सही नाम हो प्रस्तुत करने पर (प्रस्तुत अभिलेख में कांटे-छंट मान्य नहीं किया जायेगा) किया जा

सकता है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार आर्चिवायम 1969 की धारा 13(2) एवं धारा 13 (3) अधिनियम के तहत लेने वाले दस्तावेजों के तहत आवेदन, शपथ पत्र, नोटरी, पंचनामा घटना के संबंध में, घटना की परिशुद्धता प्रमाण पत्र, जन्मा-बन्मा कार्ड, स्व परीक्षण परीक्षण रिपोर्ट, आधार कार्ड-जन्म प्रकरण में माता-पिता का मृत्यु में मृतक का, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, शासकीय सेवक होने की स्थिति में सेवा पुस्तिका, शासकीय अभिलेख आवश्यक होंगे। इसके साथ ही चलिता वाहन, 108 एम्बुलेंस में मृत्यु के प्रकरण के अंतर्गत मृत्यु एक ही शहर, कस्बे या गांव के भीतर संचल वाहन या एम्बुलेंस में हुई हो अथवा सार्वजनिक निवास जैसे-स्टेशन, विमान, बस आदि में लंबी दूरी की यात्रा में मृत्यु हुई यानि मृतक स्थान के अधिकार क्षेत्र के बाहर या अन्य राज्य में हुई हो।

संक्षिप्त समाचार

जिले में एचपीव्ही टीकाकरण एवं जनजागरूकता अभियान शुरू

बिलासपुर। जिले में 14 वर्ष आयु की सभी पात्र बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल कैंसर) से बचाव के लिए एचपीव्ही वैक्सीन लगाने हेतु विशेष टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 13 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक विशेष टीकाकरण सप्ताह के रूप में संचालित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गढ़वाल ने विकासखंड तखतपुर के गिनियारी स्कूल एवं कोटा के करगीकला व गोबरीपाट स्कूल में अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं को एचपीव्ही टीके के महत्व और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई एवं उन्हें जागरूक किया। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई से तीसरे दिवस तक 1425 बालिकाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया जा चुका है। इस तरह अब तक जिले के कुल 6,136 पात्र बालिकाओं को टीका लगाया जा चुका है। यह टीका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव का प्रभावी उपाय है और गाईडेंसिल नाम के क्राइबैलेंट एचपीव्ही वैक्सीन को एक खुराक पात्र बालिकाओं को निःशुल्क दी जा रही है। सीएमएचओ ने 14 वर्ष आयु पूर्ण कर चुकीं पात्र सभी बालिकाओं के अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटीयों का एचपीव्ही टीकाकरण अवश्य कराएं, ताकि उन्हें भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके।

अंशकालिक स्पेशल एजुकेटर भर्ती, आवेदन 27 जुलाई तक

बिलासपुर। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिले के 6 पीएमसी विद्यालयों में अंशकालिक स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए 27 जुलाई 2026 तक आवेदन मंगाये गये हैं। यह भर्ती 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए होगी एवं उन्हें प्रतिमाह 20 हजार रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। प्राथमिक स्तर विद्यालय हेतु विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु विशेष शिक्षा में बीएड की डिग्री अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक 27 जुलाई 2026 तक अपना आवेदन जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, द्वितीय तल, जिला पंचायत भवन, बिलासपुर में डाक, स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवश्यक योग्यता एवं अन्य जानकारी, आवेदन पत्र प्रारूप जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला पंचायत भवन में चरप्पा की गई है।

रोजगार मेला 22 जुलाई को, 495 पदों पर होगी भर्ती

बिलासपुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी में 22 जुलाई 2026 को सवरे 11 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले में 4 निजी नियोजकों द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें लाईफमित्र, फ़ैल्ड ऑफ़िसर, कलेक्शन ऑफ़िसर, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नीशियन जैसे कुल 495 पद शामिल हैं। रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड तथा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छायाप्रति लानी होगी। मेले में शामिल होने के लिए आवेदकों को ई रोजगार पोर्टल अथवा छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से पंजीयन कर एवं रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी ई रोजगार पोर्टल, छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोनी, बिलासपुर से प्राप्त की जा सकती है।

डिप्टी कलेक्टर सालिक राम गुप्ता को भाड़ा नियंत्रक का प्रभार

बिलासपुर। डिप्टी कलेक्टर सालिक राम गुप्ता को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ आगामी आदेश तक भाड़ा नियंत्रक, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस आशय के आदेश कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने जारी किया है। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी पूर्व आदेश के संदर्भ में की गई है। आदेश के अनुसार श्री गुप्ता अपने वर्तमान कार्यों का निर्वहन करते हुए भाड़ा नियंत्रक का दायित्व भी संभालेंगे।

पात्र हितग्राहियों को नियमित मिल रहा पेंशन योजनाओं का लाभ

बिलासपुर। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जिले में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के हितग्राहियों को नियमानुसार पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। पेंशन हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से जून 2026 तक का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुढ़ावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा, दिव्यांग पेंशन के हितग्राहियों को भी माह अप्रैल 2026 तक की पेंशन राशि एसएनए-स्पर्श के माध्यम से किये जा चुके है।

महिला सशक्तिकरण की मिसाल:एसईसीएल की पूर्णतःमहिला संचालित डिस्पेंसरी ने सफलता पूर्वक पूरा किया एक वर्ष

बिलासपुर। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में एसईसीएल में शुरू की गई कोल इंडिया की प्रथम पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी, एसईसीएल के वसंत विहार डिस्पेंसरी ने अपनी स्थापना का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर आयोजित प्रथम वर्षगांठ समारोह में एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री हरीश दुहन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ केक काटकर किया गया। समारोह में वसंत विहार डिस्पेंसरी की समस्त महिला चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मों, इंदिरा हेल्थ सेंटर के चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। विगत एक वर्ष से यह डिस्पेंसरी पूर्णतः महिला चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है तथा कर्मचारियों



एवं उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएमडी श्री

हरीश दुहन ने कहा कि कोल इंडिया की प्रथम पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी एसईसीएल के लिए गर्व का विषय है।

उन्होंने कहा कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी क्षमता, नेतृत्व और कार्यकुशलता का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही

ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट में एसईसीएल ने किया कोल इंडिया का प्रतिनिधित्व

एसईसीएल निदेशक (एचआर) बिरंची दास ने ब्रिक्स मंच पर साझा किए कोल इंडिया के श्रेष्ठ एचआर मॉडल..

बिलासपुर। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता-2026 के तहत हैदराबाद में 14 से 16 जुलाई तक आयोजित हो रही ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट में साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने कोल इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) श्री बिरंची दास ने ब्रिक्स+ देशों में सर्वोत्तम प्रथाएं विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लेते हुए अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के समक्ष कोल इंडिया की मानव संसाधन, कर्मचारी कल्याण एवं सामाजिक विकास संबंधी प्रमुख पहलों को साझा किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में शामिल कोल इंडिया के 2.2 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए संचालित कर्मचारी कल्याण, महिला



सशक्तिकरण, कौशल विकास तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जन-केंद्रित

नीतियों और सहभागी कार्यसंस्कृति के माध्यम से संगठन उत्पादकता और कर्मचारी हितों के बीच संतुलन स्थापित कर रहा है। उन्होंने एसईसीएल की

सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आधारित पहलों का भी उल्लेख किया। एसईसीएल के सुफुल एवं एसईसीएल की धड़कन जैसी योजनाओं के माध्यम से

कोयलांचल क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों की जानकारी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ साझा की। उल्लेखनीय है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता-2026 की थीम रेंजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपेरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। इसी क्रम में आयोजित तीन दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय समिट में 50 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों के साथ भारतीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, श्रम विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद शामिल हुए। समिट में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, भविष्य के कार्यबल के लिए कौशल विकास, मानव-केंद्रित प्रौद्योगिकी एवं उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा बदलती कार्य दुनिया में महिलाओं की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

सेवा सेतु से आसान हुई शासकीय सेवाओं की राह,बना भरोसेमंद जनसेवा का केद्र....

■ जाति-निवास प्रमाण पत्र बनने पर रामकृष्ण ने शासन का जताया आभार

बिलासपुर। जिले में स्थापित सेवा सेतु केंद्र आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण का सशक्त माध्यम बन गया है। जिले की सोपत तहसील के ग्राम भाड़ी निवासी श्री रामकृष्ण सिन्हा को भी सेवा सेतु के माध्यम से समय पर राहत मिली। उन्होंने अपने बच्चों के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सेवा सेतु केंद्र में आवेदन दर्ज कराया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद राजस्व विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण किया और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी कर उनके बच्चों के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिए। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद श्री रामकृष्ण सिन्हा को इसकी जानकारी दी गई। आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध होने से उनके बच्चों की शैक्षणिक एवं अन्य शासकीय कार्यों में आने वाली परेशानी दूर हो गई। उन्होंने बताया कि पहले प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण उन्हें कई आवश्यक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़



रहा था, लेकिन सेवा सेतु केंद्र में आवेदन करने के बाद उनकी समस्या का शीघ्र समाधान हो गया। श्री रामकृष्ण सिन्हा ने त्वरित एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समयबद्ध कार्रवाई से उन्हें अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े और उनकी समस्या का समाधान सहज एवं सरल तरीके से हो गया।

बिलासपुर में स्कूल प्राचार्यों की बैठक, डीआईजी-एसएसपी ने सड़क सुरक्षा और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर दिए अहम निर्देश

बिलासपुर। यातायात पुलिस बिलासपुर ने सड़क सुरक्षा को जनआंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिले के शासकीय, अर्धशासकीय और निजी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं स्कूल प्रबंधकों की बैठक आयोजित की। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने स्कूलों में सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कार्यक्रम पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में आयोजित किया गया। इसमें जिले के 350 से अधिक स्कूल प्रबंधक एवं प्राचार्य शामिल हुए। बैठक में डीआईजी-एसएसपी ने सर्वोच्च न्यायालय की 18 बिंदुओं वाली स्कूल बस सुरक्षा गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से कहा कि विद्यार्थियों के स्कूल आने-जाने और परिवहन व्यवस्था में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने स्कूल परिसर और आसपास किसी भी संदिग्ध अथवा असामाजिक गतिविधि की जानकारी तत्काल संबंधित थाना पुलिस को देने की सलाह दी। साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखने, नाबालिगों द्वारा मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों के दुरुपयोग पर रोक लगाने तथा उन्हें किसी भी असामाजिक



खालते हुए कहा कि कौशल ही आत्मनिर्भरता, रोजगार एवं उवल भविष्य की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने सभी प्रशिक्षार्थियों को अपने कौशल का निरंतर विकास करने एवं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित

किया। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन एवं अंबुजा फ़उंडेशन के तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम युवाओं में कौशल विकास, नवाचार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल रहा।



स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं टाइप-2 डायबिटीज से बचें

एक अध्ययन में पाया गया है कि विटामिन-सी की खुराक लेने से मधुमेह रोगियों को दिनभर में बढ़ा हुआ रक्त शर्करा स्तर कम करने में मदद मिल सकती है। शोध में यह भी पाया गया है कि विटामिन-सी टाइप-2 डायबिटीज वाले लोगों में रक्तचाप को कम करता है, जिससे हृदय की हालत अच्छी रहती है। सच तो यह है कि शारीरिक गतिविधि, अच्छा पोषण और मधुमेह की दवाएं मानक देखभाल तथा टाइप-2 मधुमेह प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ लोगों को दवा के साथ भी अपने रक्त शर्करा के स्तर का प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में डायबिटीज से पीड़ित 25 वर्ष से कम आयु के हर चार लोगों में से एक (253 प्रतिशत) को वयस्क टाइप 2 मधुमेह है। यह स्थिति आदर्श रूप में मधुमेह, मोटापा, अस्वास्थ्यकर आहार और निष्क्रियता के पारिवारिक इतिहास वाले केवल बड़े वयस्कों को होनी चाहिए। टाइप 2 मधुमेह वाले व्यक्ति में, शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है और इस स्थिति को इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है। अग्न्याशय या पैंक्रियास पहले इसके लिए अतिरिक्त इंसुलिन बनाता है। हालांकि, समय के साथ, यह रक्त शर्करा को सामान्य स्तर पर रखने के लिए पर्याप्त नहीं बना पाता है। हालांकि इस स्थिति के

लिए सटीक ट्रिगर ज्ञात नहीं है, टाइप 2 मधुमेह कारकों के संयोजन का एक परिणाम हो सकता है। कुछ ट्रिगर आनुवंशिक रूप से इस स्थिति के लिए पूर्वनिर्धारित हो सकते हैं। मोटापे के पारिवारिक इतिहास वाले लोग इंसुलिन प्रतिरोध और मधुमेह के विकास के जोखिम में हैं। जो लोग मोटे हैं, उनके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में इंसुलिन का उपयोग करने की क्षमता पर दबाव बढ़ जाता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। किसी व्यक्ति के शरीर में जितना अधिक वसायुक्त ऊतक होते हैं, उसकी कोशिकाएं उतनी ही अधिक प्रतिरोधी होती हैं। जीवनशैली कारकों की भी इसमें प्रमुख भूमिका होती है। टाइप 2 मधुमेह के लक्षण समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होते हैं। उनमें से कुछ में प्यास और भूख में वृद्धि, बार-बार मूत्र त्याग की इच्छा होना, वजन कम होते जाना, थकान, घुघली दृष्टि, संक्रमण और घावों का धीमी गति से भर पान तथा कुछ क्षेत्रों में त्वचा का काला पड़ना शामिल हैं। स्वस्थ आहार आम तौर पर अस्वास्थ्यकर आहार की तुलना में अधिक महंगा होता है। कम पोषक तत्वों वाले सस्ते भोजन की व्यापक उपलब्धता से टाइप 2 मधुमेह की वैश्विक महामारी में इजाफा होता है। सब्जियाँ, ताजे फलों, साबुत अनाज और असंतुलित वसा जैसे टाइप 2 मधुमेह के

जोखिम को कम करने वाले खाद्य पदार्थों की व्यापक रूप से उपलब्धता और दाम कम किये जाने की आवश्यकता है। नुकसान कम करने के कुछ उपाय व्यायाम अधिक से अधिक करें। व्यायाम से विभिन्न लाभ होते हैं, जिनमें वजन बढ़ाना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और अन्य स्थितियाँ शामिल हैं। हर दिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि बहुत फायदेमंद है। रोहतमद भोजन खाएं। साबुत अनाज, फल

और सब्जियों से भरपूर आहार शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। रेशेदार भोजन यह सुनिश्चित करेगा कि आप लंबी अवधि के लिए पेट भरा महसूस करें और किसी भी तरह की तलब को रोकें। जितना हो सके, प्रोसेस्ड और रिफाईंड फूड से बचें। शराब के सेवन को सीमित करें और धूम्रपान छोड़ दें। बहुत अधिक शराब वजन बढ़ाने की ओर ले जाती है और आपके रक्तचाप और टाइप 2 डायबिटीज के स्तर को बढ़ा सकती है। पुरुषों को दो ड्रिंक प्रतिदिन और महिलाओं को एक ड्रिंक प्रतिदिन तक सीमित रखना चाहिए। धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान न करने वालों की तुलना में मधुमेह का दोगुना रिस्क रहता है। इसलिए, इस आदत को छोड़ना एक अच्छा विचार है। अपने जोखिम कारकों को समझें। ऐसा करना आपको जल्द से जल्द निवारक उपाय करने और जटिलताओं से बचने में मदद कर सकता है।



पेट में कीड़े होने का संक्रमण काफी आम है और ये बहुत ही आसानी से फैलता है। बच्चों में ये समस्या बहुत आम होती है क्योंकि वो वातावरण के लिए बहुत नए होते हैं। गलत खान-पान के कारण 1 से 14 साल के बच्चों में पेट में कीड़े होना सबसे आम समस्या होती है। ये लगभग 20 प्रकार के होते हैं जो आंतों में घाव बना सकते हैं। पेट में कीड़े होने पर पेट में गैस, बदहज्मी, दर्द और बुखार जैसी समस्या देखने को मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन समस्याओं से बचें रहें तो आप कुछ घरेलू तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चे को निरोगी जिंदगी दे सकते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े होने पर क्या-क्या लक्षण दिखने लगते हैं और शरीर पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं।

पेट में कीड़े होने के लक्षण

- बच्चों को नींद न आना और भूख न लगना।
- वजन कम होना।
- उल्टियाँ, पेट दर्द और दस्त रहना।

पेट में कीड़े होने का बुरा प्रभाव

- बच्चे को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल

- पाते।
- शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया का शिकायत हो सकती है।
- बच्चे को इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और उनका वजन भी सामान्य बच्चों से कम होता है।

बच्चों के पेट में इसलिए पड़ते हैं कीड़े घर में ऐसे करें इलाज

प्याज का रस

पेट के कीड़े नाश करने के लिए प्याज को पीस कर रस निकालें। इसे बच्चे को खाली पेट पिलाएं।

अजवायन

पेट के कीड़े खत्म करने के लिए अजवायन काफी कारगर उपाय है। इसके लिए अजवायन के आधा ग्राम चूर्ण में गुड़ डाल कर गोली बनाकर दिन में 3 बार रोगी को खिलाएं। इस उपाय

तुलसी के पते

इस उपाय को करने के लिए तुलसी के पत्तों का एक चम्मच रस दिन में दो बार

अनार के छिलके

यह उपाय बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फायदेमंद है। इसके लिए अनार के छिलकों को सुखाकर इसका चूर्ण बना लें। इसे दिन में 3 बार 1 चम्मच खाएं।

नीम के पते

नीम के पते एंटीबायोटिक होते हैं जो पेट के कीड़ों को नष्ट करने में मदद करते हैं। नीम के पत्तों को पीसकर शहद के साथ मिला कर बच्चे को खिलाएं। सुबह इसका सेवन ज्यादा फायदेमंद है।



सेहत के लिए कितना फायदेमंद कितना करेगा नुकसान

बहुत जल्द लैब में तैयार किया गया मीट या कर्चर्ड मीट आपको सुपर मार्केट में मिलने लगेगा। ऐसी खबरें हैं कि महाराष्ट्र सरकार और इन्स्टिट्यूट ऑफ कैमिकल टेक्नोलॉजी (आईसीटी) ने हाल ही में अमेरिका के एनजीओ गुड फूड इन्स्टिट्यूट (जीएफआई) के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत देश में सेल बेस्ड मीट रिसर्च और प्रडक्शन को प्रोत्साहन देने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा। कुछ लोग जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन तो अपनी डायट में शामिल करना चाहते हैं लेकिन उससे इसलिए परहेज करते हैं क्योंकि इसके लिए जानवरों को बेरहमी से मारना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए विकल्प के रूप में प्रयोगशालाओं या लैब में ही मीट तैयार करने की तकनीक विकसित की जा चुकी है। इसमें जानवरों को बिना तकलीफ पहुंचाए उनके सेल्स ले लिए जाते हैं। लैब में बायोरिएक्टर में इन सेल्स को कल्चर करके उनका ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से विकास किया जाता है। इस तरह ये सेल्स जरूरी मीट मुहैया कराते हैं। इसे ही लैब मीट या कल्चर्ड मीट कहते हैं।

क्या हैं फायदे और नुकसान
जानवरों को बिना तकलीफ पहुंचाए मीट उत्पादन की इस अगोखी तकनीक से ऐसे तमाम संगठन खुश हैं जो जानवरों पर अत्याचार का विरोध करते आए हैं। पर इसके बावजूद कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं लैब मीट के पक्ष और विपक्ष में क्या कहा जा रहा है।

फायदे
इस तकनीक के पक्षधरों का दावा है कि कल्चर्ड मीट में मनुष्यवाद बढावा करने की क्षमता की वजह से लोगों के स्वास्थ्य और पोषण पर सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए आमतौर पर मीट में सेचुरेटेड फैट होता है लेकिन कल्चर्ड मीट में उसकी जगह ओमेगा 3 फैटी एसिड और हेल्दी

फैट शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा कल्चर्ड मीट से ऐसे विटामिन और मिनेरल भी प्राप्त किए जा सकते हैं जो नेचरल मीट में कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। लैब मीट की तरफदारी करने वालों का कहना है कि लैब मीट में पोषक तत्वों को शामिल करके तमाम रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। लैब मीट चलन में आएगा तो स्लॉटर हाउस या पशु वध शालाएं बंद हो जाएंगी। इससे भी प्रदूषित मीट खाने से होने वाले रोगों से बचा जा सकेगा। चूंकि यह मीट लैब में ही तैयार किया जाएगा इसलिए जानवरों से इंसानों को होने वाले रोग भी कम से कम हो जाएंगे। अभी मीट उद्योग पर आरोप लगता है कि इससे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। पर लैब मीट चलन में आ गया तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी रुकेगा और ग्लोबल वॉर्मिंग पर भी रोक लगेगी। इन सब बातों के ऊपर जानवरों को होने वाली तकलीफ और उन पर होने वाली क्रूरता हमेशा के लिए रुक जाएगी।

नुकसान
जिन आधारों पर लैब में तैयार जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज का विरोध हो रहा है उसी तरह लैब मीट का विरोध होने लगा है। इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि यह 'अप्राकृतिक' है। कुछ लोग यह कह कर इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें हड्डी और फेट वगैरह नहीं होगा तो इसका टेस्ट नेचरल मीट की तरह नहीं होगा। लैब मीट का इस आधार पर भी विरोध हो रहा है कि चूंकि यह आसानी से मिलने वाला सस्ता मीट होगा इसलिए इसकी खपत जरूरत से ज्यादा होगी। जब लोग ज्यादा खाएंगे तो उनमें मोटापे जैसी बीमारियां होने का जोखिम भी ज्यादा होगा।

सोनी सब के 'अलादीन: नाम तो सुना होगा' में जफर बना गिनु का नया आका



सोनी सब के 'अलादीन: नाम तो सुना होगा' अपनी आकर्षक कहानी और कलाकारों के साथ दर्शकों को एक जादुई सफर पर ले जाने में कामयाब रहा है। इस शो के आगामी एपिसोड्स में दर्शकों को कुछ और रोमांच देखने को मिलेगा। गिनु (राशूल टंडन) पहले से ही अम्मिस (मिता बंसल) का सामना कर रहा है कि उन्हें इस सच का पता लग चुका है कि वही चिराग का जिनी है। उसके रास्ते में और भी परेशानियां आने वाली हैं। जब से अम्मि के सामने सच आया है, गिनु बहुत बड़े भावनात्मक तूफान से गुजर रहा है। अम्मि द्वारा उसे त्याग दिये जाने से दुखी गिनु वहां से चले जाने का फैसला करता है। अलादीन (सिद्धार्थ निगम) चिराग को राइड कर गिनु को वापस बुलाने की कोशिश करती है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि अंगूठी का जिनी अलादीन को अपने वश में करके उससे चिराग अपने कब्जे में ले लेता है। गिनु की इस अंतहीन परेशानियों में जफर (आमिर दल्वीर) अंगूठी के जिनी के जरिये चिराग को ले लेता है और अब वह जादुई चिराग को राइड कर गिनु को अपने वश में करने को तैयार है। गिनु की भूमिका निभा रहे राशूल टंडन कहते हैं, 'गिनु इस बात से बेहद दुखी है कि अम्मि ने उसे चले जाने को कहा है और वह उससे इतनी दुखी है। वैसे वह इससे भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है क्योंकि जफर के हाथ वह चिराग लगने वाला है और जल्दी ही गिनु उसके वश में होने वाला है। दर्शकों को ढेर सारे दिवस्ट और टर्न से भरपूर ट्रैक को देखने में काफी मजा आ रहा है।

देखते रहिये, 'अलादीन: नाम तो सुना होगा', सोमवार से शुक्रवार, रात 9 बजे केवल सोनी सब पर।

वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने तैयारियां सुनिश्चित करें : दिव्या मिश्रा

सभी वर्गों की सहभागिता से पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अधिक से अधिक पौधरोपण कराने के दिए निर्देश



बालोद। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को बालोद जिले में वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में उच्चायक के निर्देश दिए हैं। दिव्या मिश्रा ने कहा कि वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों की सहभागिता

से अधिक से अधिक पौधरोपण कर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य में जिले वासियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में वन मण्डलाधिकारी अभिषेक अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, अपर चंद्रकांत कौशिक एवं अन्य किशोर लकरा, संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

अपनी बेटी प्रिया के जन्मदिन पर सरिता अनमोल जैन ने रानो में कराया नेवता भोज

99 बच्चों को किया जूते एवं मोजे का वितरण

बेमेतरा। साजा विकास खण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानो में थान खम्हरिया निवासी सरिता अनमोल जैन ने दुर्ग निवासी अपनी बेटी प्रिया प्रेरक चोपड़ा के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व माध्यमिक विभाग के पूरे 99 बच्चों को जूते एवं मोजे का वितरण किया। सभी बच्चों एवं स्टाफ ने उनकी बेटी को वीडियो कॉल के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे नेवता भोज में प्राथमिक एवं माध्यमिक के सभी बच्चों को पूड़ी, सब्जी एवं जलेबी दिया। बच्चों को मध्याह्न भोजन में दाल चूवल दिया गया। नवाचारी शिक्षिका प्रतीक जैन ने बताया कि यह सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामुदायिक भागीदारी फल है। इसके माध्यम से कोई भी आम



नागरिक, समुदाय या संगठन अपने खास मौके जैसे जन्मदिन या सालगिरह आदि में सरकारी शालाओं एवं आंगनवाड़ियों में बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। इससे बच्चों को अतिरिक्त पोषण भी मिलता है, समानता की भावना विकसित होती है तथा सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत समुदाय एवं शाला के बीच आपनेपन की भावना में वृद्धि होती है। सभी बच्चों के चेहरे उज्जर पाकर खुशियों से खिल उठा। उन्होंने सरिता अनमोल जैन को धन्यवाद कहा। सरिता जी इससे पहले भी शाला में, कॉपी, पेन, कलर पेन्सिल एवं ब्रिस्कट वितरित कर चुकी हैं। आज का उनका ये आयोजन निश्चित रूप से

शाला के लिए बहुत बड़ा योगदान है। नवाचारी शिक्षिका प्रतीक जैन ने इस आयोजन के लिए पूर्व ही तैयारी कर सभी बच्चों के जूतों के नंबर उन्हें उपलब्ध कराया ताकि आसानी से बच्चों को चीजें उपलब्ध हो सकें। उन्होंने सरिता जैन को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। जिन्होंने इस कार्य के लिए 35000 रुपये की राशि खर्च की है। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य द्वािका राम वर्मा, माध्यमिक प्रधान पाठक किशुन राम साहू, प्राथमिक प्रधान पाठक उत्तम साहू, कनकलता सरसुधे, सरिता जैन, प्रतीक जैन, दीनदयाल वर्मा, प्रज्ञा जैन, अमृत गुप्ता, सभी रसीदें बहनें एवं बच्चे उपस्थित रहे।

जिले के विधायक महीने में एक दिन सिर्फ महिलाओं के लिए निकाले : प्रज्ञा निर्वाणी

बेमेतरा। महिलाओं की समस्याओं के समाधान को लेकर भाजपा महिला मोर्चा बेमेतरा ने ऐसी पहल की है, जो सफल होने पर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए जनसेवा का नया मॉडल बन सकती है, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी ने जिले के सभी विधायकों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि प्रत्येक माह एक दिन केवल महिलाओं के लिए समर्पित किया जाए, जिसमें विधायक अपनी-अपनी विधानसभा में आयोजित महिला जनसुनवाई एवं समाधान दिवस में स्वयं उपस्थित होकर महिलाओं की समस्याएं सुनें और उनके त्वरित निराकरण की प्रक्रिया शुरू कराएं। प्रज्ञा निर्वाणी ने अपने पत्र में



कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग की आवाज सीधे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, यदि हर विधायक महीने में केवल एक दिन महिलाओं को समर्पित कर दे, तो हजारों बहनों को अपनी समस्याएं

मंडलों में आयोजित की जाएगी, ताकि दूरस्थ गांवों की महिलाओं को भी अपने क्षेत्र में ही जनप्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिल सके, कार्यक्रम का संचालन भाजपा महिला मोर्चा करेगा तथा प्राप्त आवेदनों के निराकरण की

रखने, समाधान पाने और शासन-प्रशासन पर विश्वास मजबूत करने का अवसर मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार यह जन सुनवाई प्रत्येक माह विधानसभा के अलग ग - अलग ग

नियमित समीक्षा भी की जाएगी। प्रज्ञा निर्वाणी ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान केवल नारों से नहीं, बल्कि उसकी समस्याओं के समाधान से होता है, यही वास्तविक अर्थों में नारी वंदन और नारी सशक्तिकरण है, महिलाओं का मनोबल बढ़ाना, उन्हें न्याय दिलाना और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना ही इस अभियान का मूल उद्देश्य है।

इस जनसुनवाई अभियान में भाजपा महिला मोर्चा की जिला, मंडल एवं ब्यू स्तर की पदाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएंगी, साथ ही संबंधित क्षेत्र के विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष,

जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य तथा अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे, जिससे अधिकांश समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा सके। महिला मोर्चा की जिला मंत्री मनीषा शर्मा का मानना है कि यदि यह अभियान बेमेतरा जिले में सफल होता है तो इसे पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सकता है, यह पहल महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, न्याय और सुशासन से जोड़ने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा तथा जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच विश्वास का नया अध्याय लिखेगी, यह जानकारी जिला महामंत्री मधु राजपूत ने दी।

नपाध्यक्ष ने थोक चिल्लर फल व्यापारियों के साथ शहर से बाहर फल मंडी संचालित करने पर हुई चर्चा

बेमेतरा। नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा की अध्यक्षता में थोक एवं चिल्लर फल व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, आमजन की सुविधा तथा व्यापारिक गतिविधियों को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से फल दुकानों एवं थोक फल मंडी को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान फल व्यापारियों से सुझाव और राय ली गई। व्यापारियों ने भी बेहतर व्यवस्था के लिए सहयोग करने का भरपूर सहयोग दिया। इस पहल से शहर में यातायात का दबाव कम होने, बाजार व्यवस्था में सुधार आने तथा व्यापारियों एवं आम नागरिकों को



अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित वातावरण मिलने की उम्मीद जताई गई। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए सभी संबंधित पक्षों की सहमति से आगे की कार्यवाही की जाएगी, ताकि शहर के विकास और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश वर्मा सहित फल व्यापारी मौजूद रहे।

सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुरक्षा उपकरण वितरित



दुर्ग। राजहरा। नगर पालिका परिषद दुर्ग। राजहरा में नमस्ते दिवस के अवसर पर नपा अध्यक्ष तोरण लाल साहू की उपस्थिति में सीवर एवं सेंटिक टैंक सफाई में कार्य करने वाले कर्मचारियों का मुख्मन्त्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराया तथा उन्हें सुरक्षा उपकरण प्रदान किया गया। विदित हो कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से जुलाई 2023 में राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थिति की तंत्र कार्य योजना (नमस्ते) की शुरुआत की गई थी, इसके अंतर्गत पूर्व की स्वच्छता योजना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कर्मचारी, सीवर और सेंटिक टैंक कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा सुनिश्चित करना तथा सफाई कार्यों में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना है। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद दुर्ग। राजहरा के 16 सेंटिक टैंक सफाई से संबंधित कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण प्रदान किया गया। इस अवसर पर पार्षद भूपेंद्र श्रीवास, स्वास्थ्य अधिकारी राम गोपाल चंद्रकर, प्रभारी लेखपाल सुनील तारम, स्टोर प्रभारी पंकज चंद्रकर।

भिलाई निगम में 2,878 नियमितीकरण प्रकरण लंबित, विधानसभा में विधायक रिकेश ने उठाया मुद्दा

सरकार ने माना—हजारों आवेदन प्रक्रियाधीन, दस्तावेजों की कमी और जांच से हरे रही देरी

भिलाई नगर। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने विधानसभा मानसून सत्र के चतुर्थ दिवस भिलाई नगर निगम में लंबित नियमितीकरण प्रकरणों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने सरकार से लंबित आवेदनों, देरी के कारणों और प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा पर विचार मांग।

विधायक रिकेश सेन ने पूछा कि पिछले तीन वर्षों में नियमितीकरण के कितने आवेदन लंबित हैं। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि फ़हलों पर आंतिम निर्णय क्यों नहीं हो रहा। नियमितीकरण प्रक्रिया जारी है या



स्थगित कर दी गई है। साथ ही प्रक्रिया पूरी करने की निश्चित समय-सीमा बताने की मांग की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में लिखित उत्तर प्रस्तुत किया।



उन्होंने बताया कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 2,878 नियमितीकरण प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। सरकार के अनुसार अभिलेखों की जांच में समय लग रहा है।

आवश्यक दस्तावेजों की कमी भी प्रमुख कारण है। कई मामलों में स्थल निरीक्षण लंबित है। इन्हीं कारणों से आंतिम निर्णय में देरी हो रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई है। सभी प्रकरण प्रचलित कानून और नियमों के अनुसार निराकृत किए जा रहे हैं। नियमितीकरण प्रकरणों के निराकरण के लिए अलग समय-सीमा निर्धारित नहीं है। सभी मामलों का नियमानुसार और यथाशीघ्र निराकरण किया जा रहा है।

समाप्त। मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयसंतंम चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त दिवावों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahnews@gmail.com

सुपेला भिलाई पशु चिकित्सालय के जर्जर भवन पर विधायक सेन ने किया सवाल



भिलाई नगर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चतुर्थ दिवस वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सुपेला भिलाई स्थित पशु चिकित्सालय के जर्जर भवन का मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने ध्यानाकर्षण के जरिए इस अहम विषय पर सरकार से सीधे सवाल किए। विधायक ने पूछा कि क्या अत्यंत क्षतिग्रस्त हो चुके इस भवन के जीर्णोद्धार या नवीन निर्माण की कोई योजना है? उन्होंने अस्पताल में ऑपरेशन रूम, डॉक्टर रूम और शल्य चिकित्सा संचाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी की। खाली पदों पर पशु चिकित्सा सहायक विशेषज्ञों की तत्काल पदस्थापना का आग्रह किया। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में स्थिति स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया कि उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला दुर्ग द्वारा नवीन भवन निर्माण का प्रस्ताव मिला है। 10 अप्रैल 2026 को प्राप्त यह प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। हालांकि, विभागीय मंत्री ने नए संसाधनों और पदों की वृद्धि के संबंध में कोई भी निश्चित समय-सीमा बताने में असमर्थता जताई।

सिटी प्रेस क्लब ने पूर्व एसपी को दी भावभीनी विदाई, नवागत एसपी का अभिनंदन

मीडिया और पुलिस की साझेदारी से अपराध नियंत्रण होगा, जनता का विश्वास सर्वोच्च प्राथमिकता : एस पी बंसल



बेमेतरा। सिटी प्रेस क्लब की ओर से पूर्व पुलिस अधीक्षक एवं वर्तमान डीआईजी रामकृष्ण साहू को भावभीनी विदाई तथा नवागत पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के सम्मान में गरिमायक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों और पुलिस अधिकारियों ने जिले में बेहतर पुलिसिंग, पारदर्शिता और मीडिया-पुलिस समन्वय को लेकर अपने विचार साझा किए। समारोह में सदस्य दिनेश दुबे एवं वक्ताओं ने पूर्व एसपी रामकृष्ण साहू के करीब दो वर्ष छह

माह के कार्यकाल को जिले के सबसे लंबे और उल्लेखनीय कार्यकालों में से एक बताते हुए उनकी कार्यशैली, संवेदनशीलता और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों की सराहना की। पत्रकारों ने कहा कि उनके कार्यकाल में पुलिस और मीडिया के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित हुआ, जिससे कई मामलों में अपराध नियंत्रण और जनजागरूकता को मजबूती मिली। पत्रकार दिनेश दत्त दुबे, योगेश राजपूत, आनंद साहू, अरुण सोनी, अनीश मेमन खिलेश

धृतराज एवं ममता ग्वालवंशी आशीष कटले, अरविंद गोस्वामी ने भी साहू के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अमीन पणु रवानी ने नवागत पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल का स्वागत करते हुए कहा कि जिले को उनके अनुभव और ऊर्जा का लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस और मीडिया के बीच समन्वय की परंपरा आगे भी मजबूत होगी तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग जारी रहेगा।

मीडिया के सहयोग से होगी बेहतर पुलिसिंग : त्रिलोक बंसल अपने संबोधन में नवागत पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है और समाज तथा प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, साइबर अपराधों की रोकथाम और जनजागरूकता जैसे विषयों पर पुलिस को मीडिया का सकारात्मक सहयोग हमेशा मिलता रहा है। उन्होंने कहा, मेरी प्राथमिकता आम नागरिकों की सुरक्षा, त्वरित कार्रवाई और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था रहेगी। मीडिया के साथ नियमित संवाद बनाए रखा जाएगा, ताकि सही जानकारी समय पर लोगों तक पहुंचे और समाज में विश्वास का वातावरण मजबूत हो। पुलिस और मीडिया मिलकर जनहित में बेहतर कार्य करेंगे।

मीडिया का सहयोग हमेशा याद रहेगा : रामकृष्ण साहू

पूर्व पुलिस अधीक्षक एवं वर्तमान डीआईजी रामकृष्ण साहू ने कहा कि बेमेतरा में मिले सहयोग को वे हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि अपने पूरे कार्यकाल में उनका प्रयास सकारात्मक सोच के साथ पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने का रहा। अपराधों की रोकथाम, जनजागरूकता और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मीडिया ने हमेशा रचनात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण के बाद भी उनका आसीम रिश्ता बेमेतरा और यहां के पत्रकारों से बना रहेगा। आयोजन के लिए उन्होंने सिटी प्रेस क्लब का आभार व्यक्त किया। समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव, यातायात प्रभारी खलको, थाना प्रभारी सोनल ग्वाला सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं सिटी प्रेस क्लब के सदस्य मेडी धीवर, आकाश रेहरा, दीपेश राजपूत, अजीत राजपूत, अमित, भरत, ताम्रध्वज साहू सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पूर्व एसपी रामकृष्ण साहू को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई तथा नवागत एसपी त्रिलोक बंसल का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया।